facebook.com/thebharatshri
twitter.com/thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 22 दिसंबर 2025 ● वर्ष 7 ● अंक 23 ● मूल्यः 5 रुपए

त्वचा रोग का आयुर्वेदिक इलाज

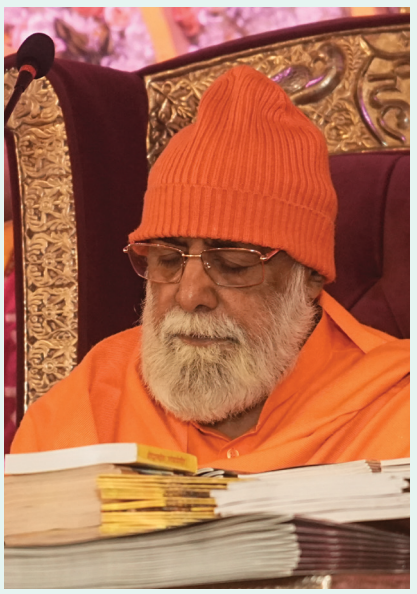

रक्षा के लिए मां से करें प्रार्थना

पेज-10-11

सद्गुरु वाणी

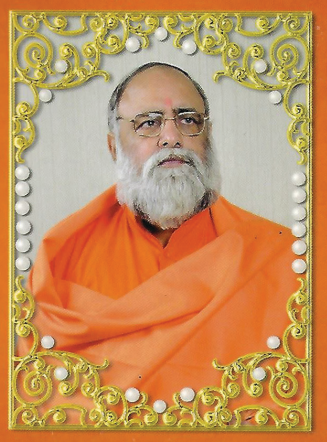

दिव्य पाठ प्रभु कृपा का वह आलोक है जिसे करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन तपस्या या साधना की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़ा सहज और सरल है।

●

परमात्मा की नजर में सभी भाई-बहन बराबर हैं। परमात्मा जाति, धर्म, देश, सम्प्रदाय से पार है। हमें सभी भाई-बहनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए।

●

विश्व भर में होने वाले प्रभु कृपा दुख निवारण समागम केवल प्रभु की कृपा से संभव होते हैं। इसका आयोजन कोई व्यक्ति नहीं करता।

दिल्ली की सड़कों पर उठा आक्रोश

ढाका तक पहुंची गूंज

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

@ भारतश्री ब्यूरो

नई दिल्ली की सुबह सामान्य नहीं थी। बांग्लादेश हाई कमिशन के सामने जमा होती भीड़, हाथों में बैनर-पोस्टर, आंखों में गुस्सा और आवाज़ में दर्द साफ बता रहा था कि मामला सिर्फ एक प्रदर्शन भर नहीं है। यह उस पीड़ा का विस्फोट था, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, घरों और मंदिरों में सुलग रही थी।विश्व हिंदू परिषद और कई अन्य हिंदू संगठनों ने बुधवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध का केंद्र बना बांग्लादेश हाई कमिशन, जहां सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात था। बावजूद इसके, प्रदर्शनकारियों का आक्रोश इतना तीखा था कि कई बार हालात तनावपूर्ण हो गए।

एक हत्या, जिसने सीमाएं लांघ दीं

प्रदर्शन की जड़ में बांग्लादेश की एक भयावह घटना है। जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक को उग्र भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। यहीं नहीं रुकी हिंसा। आरोप है कि उसके शव को चौराहे पर लटकाया गया, लाठियों से पीटा गया और बाद में आग के हवाले कर दिया गया।इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने भारत ही नहीं, पड़ोसी नेपाल तक में आक्रोश फैला दिया। वीडियो में दिख रही बर्बरता ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया। यही वजह रही कि विरोध अब डिजिटल दुनिया से निकलकर सड़कों पर आ गया।

दिल्ली में उमड़ा जनाक्रोश

नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमिशन के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों में साधारण नागरिक, संत-महात्मा, महिलाएं और युवा शामिल थे। सभी के हाथों में एक ही संदेश था ,बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद हों।प्रदर्शनकारी बैनरों पर लिखे नारों के जरिए अपनी बात रख रहे थे। कहीं दीपू चंद्र दास की तस्वीर थी, कहीं लिखा था "हिंदुओं की हत्या बंद करो", तो कहीं "मानवाधिकार कहां हैं" जैसे सवाल।एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि हम किसी को मारने वाले लोग नहीं हैं। ये देश राम और कृष्ण का है। लेकिन वहां हमारी बहन-बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे बच्चों को जिंदा जला दिया जा रहा है।

सुरक्षा घेरा और टूटता सब्र

दिल्ली पुलिस ने हालात की गंभीरता को देखते हुए हाई कमिशन के सामने दो-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया था। बैरिकेड्स लगाए गए थे, अतिरिक्त बल तैनात था। लेकिन जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, गुस्सा भी बढ़ता गया।कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस को उन्हें रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई बार धक्का-मुक्की हुई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि, स्थिति को काबू में रखा गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, भीड़ भावनात्मक रूप से बहुत आहत थी। ऐसे में संयम बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हालात नियंत्रण में हैं।

"मैं भी दीपू हूं"

प्रदर्शन के दौरान एक नारा बार-बार सुनाई दिया कि मैं भी दीपू हूं, आप भी दीपू हैं।यह नारा सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि डर और एकजुटता की भावना का प्रतीक बन गया।एक युवा प्रदर्शनकारी ने कहा कि आज दीपू को मारा गया है, कल कोई और होगा। अगर हम आज नहीं बोले, तो कल बहुत देर हो जाएगी।प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला भी जलाया और उनके खिलाफ नारे लगाए। उनका आरोप था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है।

नेपाल तक फैला विरोध

इस घटना का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। नेपाल में भी हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। काठमांडू समेत कई शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई गई। इससे साफ हो गया कि मामला अब क्षेत्रीय चिंता का विषय बन चुका है।दिल्ली में प्रदर्शन और हाई कमिशन के बाहर बढ़ते तनाव पर बांग्लादेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ढाका ने नई दिल्ली में भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया और अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।बांग्लादेश सरकार का कहना है कि किसी भी देश के राजनयिक मिशन की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय दायित्व है। ढाका ने यह भी कहा कि नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में उसके मिशन के बाहर हो रहे प्रदर्शनों से वह चिंतित है।

सवाल जो हवा में तैर रहे हैं

इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति वाकई सुरक्षित है। क्या वहां की सरकार ऐसी घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। और सबसे अहम, क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर आंख मूंदे रहेगा।प्रदर्शन कर रहे संगठनों का कहना है कि वे किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि मानवता के पक्ष में खड़े हैं। उनका दावा है कि अगर आज आवाज नहीं उठाई गई, तो हालात और बिगड़ेंगे।शाम होते-होते प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन सवाल और आक्रोश वहीं रह गए। बांग्लादेश हाई कमिशन के सामने खाली सड़कें गवाही दे रही थीं कि यह सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं है, बल्कि लंबे समय से जमा पीड़ा का परिणाम है।

MN DIVINE

ORDER ALL TYPES OF :

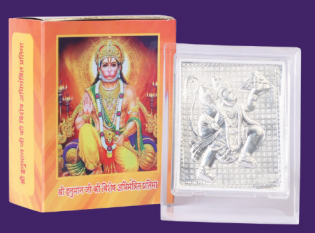

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.

NOW GET AT YOUR HOME ON

MNDIVINE.COM

ORDER NOW

https://mndivine.com/

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

ड्रग नेटवर्क पर योगी का अल्टीमेटम

विधानसभा में योगी का तीखा तेवर, माफिया से लेकर सियासत तक खुली जंग

@ अभिषेक चौबे

उत्तर प्रदेश विधानसभा का माहौल सोमवार को उस वक्त अचानक गर्म हो गया, जब कोडीन कफ सिरप मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला बोला। बात सिर्फ एक ड्रग रैकेट की नहीं रही, बल्कि सियासत, माफिया और पुराने सत्ता संबंधों तक जा पहुंची। मुख्यमंत्री के शब्दों में गुस्सा भी था, चेतावनी भी और यह संदेश भी कि कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है।योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कोडीन कफ सिरप के इस पूरे मामले की जड़ें पिछली सरकार के दौर में दी गईं लाइसेंस व्यवस्था से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, विभोर राणा को जो लाइसेंस मिला था, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे नेटवर्क के तार सीधे सपा से जुड़े लोगों तक पहुंचते हैं।

"किसी को बख्शा नहीं जाएगा"

विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अब तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कार्रवाई लगातार जारी है। NDPS एक्ट के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। योगी ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की जांच के लिए राज्य के IG लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाई गई है, जो पूरे प्रदेश में नेटवर्क की कड़ियों को जोड़कर कार्रवाई कर रही है।

फातिहा पढ़ने का मौका भी नहीं देंगे

मुख्यमंत्री के भाषण का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला हिस्सा उनका वह बयान रहा, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर सीधा हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मैं आपका दर्द समझता हूं। क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचेगी, तो आप में से कई लोग फातिहा पढ़ने जाएंगे। लेकिन हम आपको ऐसी हालत में भी नहीं छोड़ेंगे कि आप फातिहा पढ़ सकें।यह बयान सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही तल्खी को और गहरा करता दिखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह पता है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि वह लंबे समय तक इसी तंत्र के साथ रही है। उनके मुताबिक, विपक्ष की घबराहट इसी बात का संकेत है कि कार्रवाई सही दिशा में जा रही है।

माफिया और सियासत का रिश्ता

योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में माफिया और सियासत के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शैली ट्रेडर्स का शुभम जायसवाल, जो इस केस में एक बड़ा नाम है, समाजवादी पार्टी युवजन सभा का प्रदेश सचिव है। इतना ही नहीं, वह कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे अमित यादव का बिजनेस पार्टनर भी है।मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी कहा कि अमित यादव की तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं और वह पार्टी का पदाधिकारी है। योगी ने कहा कि आप इससे इनकार नहीं कर सकते। यूपी में सबसे बड़ा स्टॉक रखने वाला यही व्यक्ति है, और उसके राजनीतिक कनेक्शन साफ दिखाई देते हैं।"

वायरल तस्वीरों का जिक्र

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आलोक सिपाही का भी जिक्र किया, जो इस मामले में एक आरोपी है। योगी के मुताबिक, आलोक सिपाही की अखिलेश यादव के साथ गिफ्ट देते हुए तस्वीरें वायरल हुई थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तस्वीरें सिर्फ इत्तेफाक नहीं हैं, बल्कि यह दिखाती हैं कि किस तरह से राजनीतिक संरक्षण में ऐसे नेटवर्क फलते-फूलते रहे।

"कोडीन से यूपी में एक भी मौत नहीं"

जहां एक ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर था, वहीं मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ जवाब देने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप या नकली दवाओं से एक भी मौत नहीं हुई है।प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र सरकार के संज्ञान में कोडीन से मौत का एक भी मामला नहीं आया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप का उत्पादन नहीं होता।

उत्पादन दूसरे राज्यों में

मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी में केवल कोडीन कफ सिरप के स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं। इसका उत्पादन मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में होता है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में मौत के मामले सामने आए हैं, वे सभी उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं।योगी ने कहा कि सरकार तथ्यों के आधार पर बात कर रही है और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विपक्ष के सवाल और सरकार का जवाब

विधानसभा में विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर कोडीन कफ सिरप का इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, तो इसके सामाजिक असर क्या हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे नेटवर्क को पनपने से रोकना भी है।उन्होंने कहा कि दवाओं की सप्लाई चेन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और लाइसेंस प्रणाली को पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है।योगी आदित्यनाथ ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। SIT पूरे प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर जांच कर रही है और जैसे-जैसे सबूत सामने आएंगे, वैसे-वैसे गिरफ्तारी होती रहेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी दबाव में नहीं है और न ही किसी राजनीतिक पहचान के आधार पर किसी को राहत दी जाएगी।

ड्रग नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण

कोडीन कफ सिरप मामला अब सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं रहा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सख्ती और जवाबदेही का प्रतीक बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के जरिए साफ संदेश दिया कि माफिया, ड्रग नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण की त्रयी को तोड़ने के लिए सरकार पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। विधानसभा में दिया गया यह बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा। एक ओर विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है, तो दूसरी ओर सरकार इसे कानून व्यवस्था और जनहित से जोड़कर पेश कर रही है।फिलहाल इतना तय है कि कोडीन कफ सिरप मामला अभी थमा नहीं है। जांच जारी है, कार्रवाई चल रही है और इसके सियासी असर आने वाले समय में और गहरे दिखाई दे सकते हैं।

Viksit Bharat–G RAM G बिल 2025

ग्रामीण रोजगार को नई उड़ान

बिल का सफर: पुराने कानून को अलविदा, नई शुरुआत की ओर

भारत सरकार ने हाल ही में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 को संसद से पास कराया है, जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले पुराने कानून महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (एमजीएनआरईजीए) की जगह लेगा। यह बिल विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए बनाया गया है, जहां ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। पुराने कानून ने 2005 से लाखों ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का काम दिया था, लेकिन अब नया बिल इसे 125 दिनों तक बढ़ा रहा है। साथ ही, यह योजना को सिर्फ वेलफेयर से आगे ले जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के कामों से जोड़ रहा है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि बिल में 60 दिनों का ऐसा समय रखा गया है जब काम नहीं दिया जाएगा, ताकि बुआई और कटाई के मौसम में मजदूर खेतों में उपलब्ध रहें। फंडिंग का तरीका भी बदल गया है- पहले डिमांड पर आधारित था, अब नॉर्मेटिव फंडिंग से सालाना 1.51 लाख करोड़ रुपये का बजट तय होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,700 करोड़ के करीब है। राज्य सरकारों को 60:40 के अनुपात में योगदान देना होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को ज्यादा मदद मिलेगी। यह बदलाव ग्रामीण पंचायतों को प्लानिंग का अधिकार देगा, जहां विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बनेंगे और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं से जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नया कदम ग्रामीणों की जिंदगी में वाकई बदलाव लाएगा, या सिर्फ कागजों पर रह जाएगा? कुल मिलाकर, यह बिल ग्रामीण रोजगार को विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश है, जो आने वाले वर्षों में देश की ग्रामीण तस्वीर बदल सकता है।

रोजगार की नई गारंटी: 125 दिन काम, लेकिन शर्तों के साथ

नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का है, जो ग्रामीण परिवारों के लिए ज्यादा कमाई का मौका देगा। हर वयस्क सदस्य को अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए यह गारंटी मिलेगी, लेकिन अगर 15 दिनों में काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। वेतन का भुगतान हफ्ते में या 15 दिनों के अंदर डिजिटल तरीके से होगा, जो पुराने सिस्टम की देरी को कम करेगा। बिल चार मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करता है- जल सुरक्षा के काम जैसे तालाब बनाना, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और भंडारण, आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट्स और मौसम की मार से बचाव के विशेष काम। इससे बने एसेट्स को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में जोड़ा जाएगा, जो पूरे देश की एकसमान रणनीति बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च को 6% से बढ़ाकर 9% करने से स्टाफिंग, ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट बेहतर होगा। ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल और स्टीयरिंग कमिटी बनेंगी, जो पंचायती राज को मजबूत करेंगी। सोशल ऑडिट साल में कम से कम दो बार होंगे, जीपीएस मॉनिटरिंग और रीयल-टाइम डैशबोर्ड से पारदर्शिता आएगी। डिजिटल अटेंडेंस और आधार-बेस्ड सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि मिसअप्रोप्रिएशन और मशीनों का गलत इस्तेमाल रुके। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण आय बढ़ेगी, गरीबी कम होगी और लाइवलीहुड डाइवर्सिफाई होगा। लेकिन क्या ये बदलाव जमीनी स्तर पर लागू होंगे? कुल मिलाकर, यह बिल रोजगार को सिर्फ तात्कालिक मदद से ऊपर उठाकर लंबे समय के विकास से जोड़ रहा है, जो ग्रामीणों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है अगर सही से चले।

ग्रामीण मजदूरों की जिंदगी में बदलाव: फायदे और फंसाव

ग्रामीण मजदूरों के लिए यह बिल नई उम्मीदें जगाता है, क्योंकि 125 दिनों का काम उन्हें साल भर स्थिर आय देगा, खासकर उन परिवारों को जो खेती पर निर्भर हैं। इससे बनी इरिगेशन, वॉटर कंजर्वेशन और कनेक्टिविटी वाली चीजें किसानों की मदद करेंगी, ताकि मजदूरों को खेतों में ज्यादा जरूरत पड़े। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के काम ग्रामीण इलाकों को मजबूत बनाएंगे, जैसे बाढ़ या सूखे से बचाव। महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी, जो आय असुरक्षा को कम करेगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं- नॉर्मेटिव फंडिंग से अगर संसाधन कम पड़े तो काम की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बढ़ोतरी से अगर स्टाफ न बढ़े तो प्लानिंग में देरी हो सकती है। 60 दिनों का नो-वर्क पीरियड अच्छा है, लेकिन इसका सही प्रबंधन न हो तो मजदूरों को परेशानी हो सकती है। पॉस्ट-पैंडेमिक समय में पूरे दिन काम पूरा न होने की समस्या बनी हुई है, जिसे डिजिटल टूल्स से हल करने की कोशिश है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिर होगी, लेकिन क्या यह सब ग्रामीणों तक पहुंचेगा? बिल ग्रामीण रोजगार को सेफ्टी नेट से डेवलपमेंट टूल में बदल रहा है, जो गरीबी घटाने और आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। कुल मिलाकर, मजदूरों के लिए यह अवसरों का द्वार खोलता है, लेकिन सफलता जमीनी अमल पर निर्भर करेगी।

विपक्ष की आवाज: पुराने अधिकारों पर सवाल, केंद्र की पकड़ बढ़ी?

विपक्षी दलों ने इस बिल को जमकर आलोचना की है, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे 'एंटी-विलेज' बताया और कहा कि यह 20 साल के एमजीएनआरईजीए को एक दिन में तोड़ रहा है। उनका कहना है कि बिल मजदूरों के काम का कानूनी अधिकार कमजोर कर रहा है, ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता घटा रहा है और केंद्र को ज्यादा कंट्रोल दे रहा है। महात्मा गांधी का नाम हटाने को राष्ट्रपिता का अपमान बताया गया, साथ ही हिंदी थोपने का आरोप भी लगाया। टीडीपी और अन्य पार्टियों ने राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की बात कही, क्योंकि 60:40 फंडिंग से राज्यों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। संसद में हंगामा हुआ, विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़ी, वॉकआउट किया और धरना दिया। एक्टिविस्ट्स का मानना है कि यह बिल एमजीएनआरईजीए के मूल सिद्धांतों को कमजोर कर रहा है, जैसे डिमांड-ड्रिवन स्कीम को नॉर्मेटिव में बदलना, जो संसाधनों की अनिश्चितता लाएगा। वे कहते हैं कि जल्दबाजी में बिल पास किया गया, बिना पर्याप्त चर्चा के। लेकिन सरकार का पक्ष है कि यह सुधार विकसित भारत के लिए जरूरी है, पारदर्शिता बढ़ाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगा। क्या विपक्ष की चिंताएं जायज हैं या यह प्रगति का रास्ता है? यह बहस ग्रामीण नीतियों के भविष्य को आकार देगी। कुल मिलाकर, बिल के दोनों पहलुओं को देखते हुए संतुलित नजरिया अपनाना होगा।

भविष्य की तस्वीर: ग्रामीण भारत की विकसित यात्रा शुरू?

यह बिल ग्रामीण रोजगार को नई दिशा दे सकता है, अगर चुनौतियों को समय पर हल किया जाए। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जो आर्थिक विकास को गति देगा। डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑडिट से भ्रष्टाचार कम होगा, जबकि पंचायतों को प्लानिंग का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करेगा। लेकिन सफलता के लिए राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल जरूरी है, साथ ही ट्रेनिंग और संसाधनों का सही वितरण। क्या यह बिल ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा या नई समस्याएं खड़ी करेगा? आने वाले सालों में इसका असर दिखेगा, जब एसेट्स बनेंगे और आय बढ़ेगी। सरकार को विपक्ष की बातों पर गौर करना चाहिए, ताकि सभी पक्षों का भला हो। कुल मिलाकर, यह कदम ग्रामीण भारत को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि विकास सबके लिए समान कैसे हो।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

मोबाइल रिचार्ज फिर महंगा: कब बढ़ेंगे दाम, कितना बोझ पड़ेगा जेब पर, कंपनियां क्यों कर रही बार-बार यह खेल

भारत के मोबाइल यूजर्स के लिए एक नई मुसीबत दस्तक दे रही है। मोरगन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अगले साल अप्रैल से जून तक अपने 4जी और 5जी प्लान्स के दाम 16 से 20 फीसदी तक बढ़ा सकती हैं। यह बढ़ोतरी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के प्लान्स पर लागू होगी, जिससे करोड़ों यूजर्स की जेब पर असर पड़ेगा। याद रहे, जुलाई 2024 में इन्हीं कंपनियों ने 10 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन 2025 में उन्होंने चुपके से प्लान्स के फायदे घटाकर लागत ऊंची की। अब 2026 में यह चौथी बड़ी छलांग होगी, जो आठ सालों में सबसे ज्यादा बार हो रही है। पहले 2019 में 15 से 50 फीसदी, फिर 2021 में 20 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट कहती है कि यह कदम कंपनियों को औसत कमाई प्रति यूजर (एआरपीयू) बढ़ाने में मदद करेगा, जो फिलहाल दक्षिण-पूर्व एशिया के मुकाबले काफी कम है। जियो और एयरटेल जैसे मजबूत खिलाड़ी इससे फायदा उठाएंगे, जबकि वोडाफोन आइडिया को नुकसान हो सकता है। यूजर्स को अब सोचना पड़ेगा कि क्या 199 रुपये का मंथली प्लान 222 रुपये हो जाए या 899 वाला 1006 रुपये का। यह बदलाव 5जी नेटवर्क को पैसे कमाने लायक बनाने के लिए जरूरी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी अनलिमिटेड 5जी डेटा मुफ्त मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्राहक इतनी जल्दी तैयार हैं? कुल मिलाकर, यह बढ़ोतरी बाजार की हवा बदलेगी, लेकिन आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डालेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

आने वाली बढ़ोतरी का पूरा राज: कब, कितना और किस पर असर

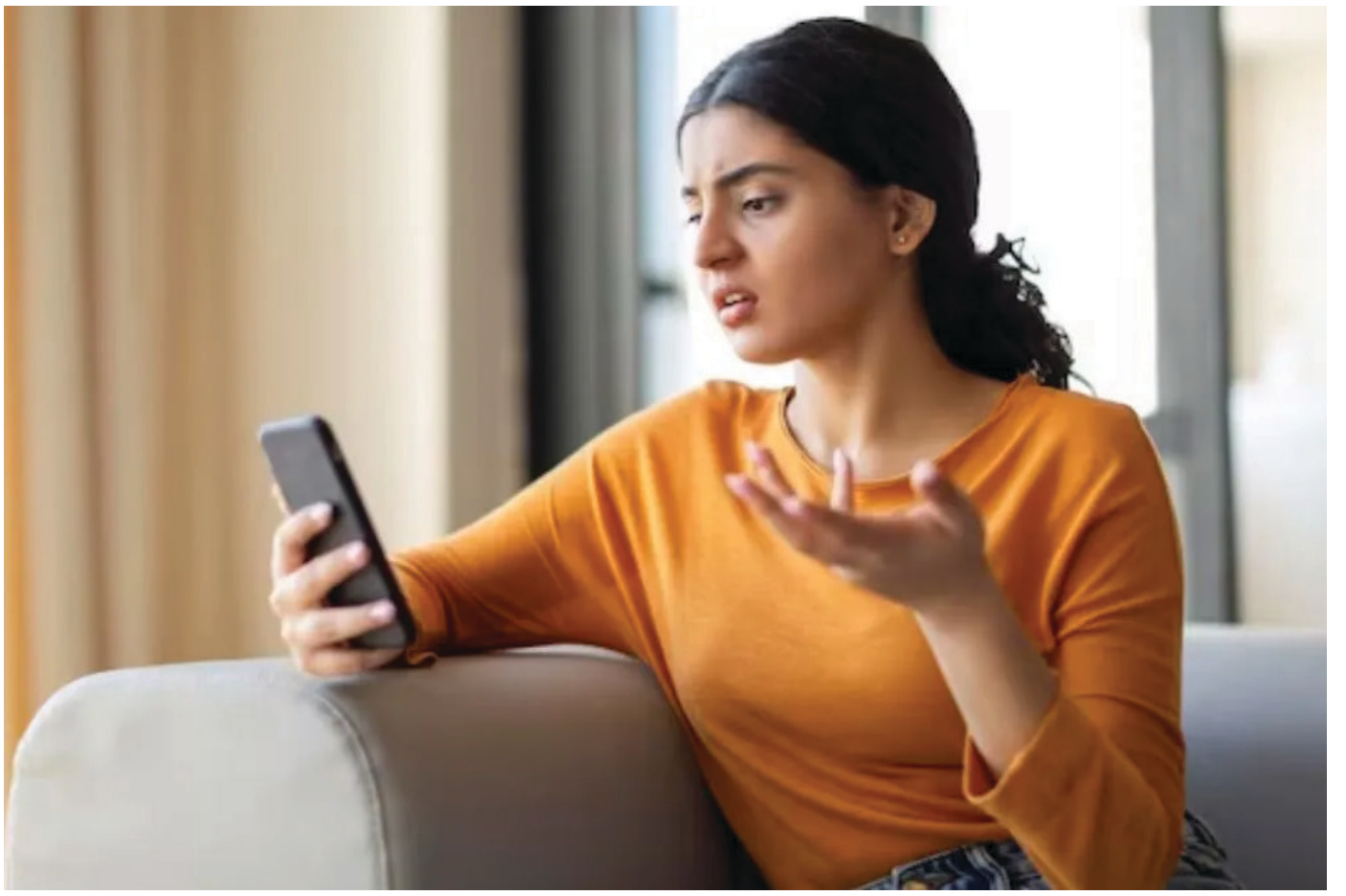

बार-बार दाम ऊपर क्यों? टेलीकॉम की पुरानी कहानी और नई मजबूरियां

टेलीकॉम कंपनियां दाम क्यों बढ़ा रही हैं इतनी तेजी से, यह समझना आसान नहीं। आठ सालों में तीन बड़ी बढ़ोतरी के बाद अब चौथी की तैयारी, इसका पीछा कई वजहें हैं। सबसे बड़ी बात 5जी नेटवर्क का खर्चा है, जो अरबों रुपये का बोझ डाल रहा। कंपनियां इसे लगाने के बाद अब पैसे वसूलना चाहती हैं, इसलिए अनलिमिटेड 5जी को महंगे प्लान्स तक सीमित कर रही हैं। दूसरी वजह एजीआर बकाया और सरकारी ड्यूज हैं, जो वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को तोड़ रहे हैं। मोरगन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का एआरपीयू बहुत कम है, जिससे कंपनियां घाटे में चल रही। तुलना करें तो फिलीपींस जैसे देशों में यह दोगुना है। कंपनियां सस्ते प्लान्स हटा रही हैं और ओटीटी सर्विसेज को प्रीमियम पैकेज में डाल रही हैं, ताकि यूजर्स ऊंचे दाम वाले प्लान चुनें। 2025 में कोई खुली बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन फायदे घटाकर चुपचाप लागत ऊंची की गई। अब 2026 में खुला खेल होगा, क्योंकि दो साल का टैरिफ चक्र खत्म हो रहा। इतनी जल्दी बढ़ोतरी इसलिए भी, क्योंकि कैपिटल खर्चा घट रहा है, लेकिन डेटा इस्तेमाल बढ़ रहा। ग्राहक फोन से फीचर फोन पर, प्रीपेड से पोस्टपेड पर शिफ्ट हो रहे, जो एआरपीयू बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सही रास्ता है? कंपनियां कहती हैं कि सस्ते दाम से क्वालिटी प्रभावित हो रही, लेकिन यूजर्स पूछते हैं कि कब तक यह सिलसिला चलेगा। कुल मिलाकर, यह बाजार की पुरानी लड़ाई है, जहां लाभ और सेवा का बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा।

ग्राहकों की जेब पर बोझ: बढ़ते दामों से रोजमर्रा कैसे बदलेगी जिंदगी

मोबाइल रिचार्ज महंगा होने से सबसे ज्यादा फर्क आम यूजर को पड़ेगा, खासकर उन परिवारों पर जो मध्यम वर्ग के हैं। कल्पना करें, आपका 28 दिन का 1.5 जीबी डेटा वाला प्लान 50 रुपये महंगा हो जाए, तो महीने में 150 रुपये अतिरिक्त खर्च। मोरगन स्टैनली के अनुमान से 16-20 फीसदी बढ़ोतरी से 12 करोड़ प्रीपेड यूजर्स प्रभावित होंगे। गांवों में जहां लोग सस्ते प्लान पर निर्भर हैं, वहां यह झटका और गहरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ, कंपनियां कहती हैं कि बेहतर 5जी स्पीड और कवरेज मिलेगा, जो लंबे समय में फायदेमंद। 2024 की बढ़ोतरी के बाद भी सब्सक्राइबर बेस बढ़ा, क्योंकि सेवा सुधरी। वोडाफोन आइडिया के यूजर्स सबसे ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि उनकी बाजार हिस्सेदारी 29 से घटकर 22.5 फीसदी रह सकती है। एयरटेल और जियो के यूजर्स को शायद कम झटका लगे, लेकिन कुल मिलाकर महंगाई के दौर में यह बोझ बढ़ाएगा। सवाल यह है कि क्या ग्राहक कंपनियों का दबाव झेल पाएंगे? कई लोग अब बीएसएनएल जैसे सस्ते विकल्प तलाश रहे, जो 2025 में दाम नहीं बढ़ा। लेकिन बीएसएनएल की सेवा क्वालिटी पर सवाल हैं। कुल प्रभाव यह कि शहरी यूजर्स ओटीटी बंडलिंग से खुश हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में डेटा एक्सेस सीमित हो सकता है। यह बदलाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक की दौड़ में आम आदमी पीछे न छूट जाए। बैलेंस्ड नजरिए से देखें तो बढ़ोतरी जरूरी है, लेकिन पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।

कंपनियों की मजबूरी: लाभ की होड़ में क्यों फंस गई टेलीकॉम इंडस्ट्री

टेलीकॉम कंपनियां दाम बढ़ाकर क्या हासिल कर रही हैं, यह उनकी मजबूरी की कहानी बयान करता है। जियो और एयरटेल जैसी लीडर्स 2026 की बढ़ोतरी से अपनी कमाई हिस्सा 36 से बढ़ाकर 40 फीसदी कर लेंगी, जबकि वोडाफोन आइडिया 24 से घटकर 18 फीसदी पर सिमट जाएगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 5जी निवेश के बाद अब मोनेटाइजेशन का वक्त है, क्योंकि डेटा प्राइस प्रति जीबी बहुत कम है। कंपनियां प्रीपेड यूजर्स को पोस्टपेड पर शिफ्ट कर रही, जो ज्यादा कमाई देता। इंटरनेशनल रोमिंग और स्मार्टफोन अपग्रेड भी एआरपीयू बढ़ाने के हथकंडे हैं। लेकिन क्यों इतनी जल्दी? क्योंकि इंडस्ट्री का एआरपीयू 370-390 रुपये तक पहुंचना चाहिए, जो फिलहाल आधा है। 2019, 2021 और 2024 की बढ़ोतरी से मजबूत कंपनियां फायदे में रहीं, लेकिन कमजोर खिलाड़ी पिछड़ गए। अब 2026 में भी यही पैटर्न दोहराएगा। सरकार की पॉलिसी ने भारत को दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम बाजार बनाया, लेकिन कंपनियों को घाटा हो रहा। ट्राई रेगुलेशंस ने लागत कम रखी, लेकिन अब बैलेंस बनाने का दबाव है। सवाल उठता है कि क्या यह होड़ यूजर्स के हित में है? कंपनियां कहती हैं कि बिना बढ़ोतरी के नई तकनीक नहीं ला सकतीं। लेकिन बैलेंस्ड दृष्टि से, यह इंडस्ट्री की परिपक्वता की निशानी है, जहां लाभ और सेवा दोनों को संभालना पड़ेगा। आगे सैटेलाइट इंटरनेट जैसे नए विकल्प आ सकते हैं, जो दामों को नियंत्रित करें।

आगे की राह: यूजर्स के लिए सलाह और बाजार का भविष्य

अब जब बढ़ोतरी तय लग रही, तो यूजर्स क्या करें? सबसे पहले, मौजूदा सस्ते प्लान्स को लंबे समय के लिए रिचार्ज कर लें, ताकि नई दरें बाद में लागू हों। बीएसएनएल जैसे विकल्प देखें, जो दाम नहीं बढ़ा रहा, लेकिन स्पीड चेक करें। पोस्टपेड पर शिफ्ट करने से फायदे मिल सकते हैं, जैसे बेहतर कस्टमर केयर। कंपनियां ओटीटी बंडलिंग बढ़ा रही, तो फैमिली प्लान चुनें जो कई डिवाइस कवर करें। भविष्य में 2026 तक सैटेलाइट इंटरनेट रोलआउट होगा, जो ग्रामीण इलाकों में सस्ता कनेक्शन लाएगा। मोरगन स्टैनली का अनुमान है कि एआरपीयू बढ़ने से इंडस्ट्री मजबूत होगी, लेकिन सरकार को ट्राई के जरिए निगरानी रखनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या यूजर्स की आवाज सुनी जाएगी? बैलेंस्ड नजरिए से, बढ़ोतरी सेवा सुधार लाएगी, लेकिन ज्यादा न हो। कंपनियां और रेगुलेटर मिलकर ऐसा मॉडल बनाएं जहां तकनीक सबके पहुंच में हो। कुल मिलाकर, यह बदलाव हमें जागरूक बनाता है कि मोबाइल सिर्फ फोन नहीं, जिंदगी का हिस्सा है। स्मार्ट चॉइस से बोझ कम किया जा सकता है।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 22 दिसंबर 2025, विक्रम संवत 2080

राहुल गांधी के बयान और हिंदुत्व–लोकतंत्र की बहस

राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं जर्मनी के बैंकॉक शहर में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण में तीन बातें प्रमुख प्रमुख रूप से कही । पहली बात उन्होंने यह कहीं की भारत में हर जगह संघ के लोग बैठ रहे हैं न्यायपालिका चुनाव आयोग कार्यपालिका विधायिका सब जगह संघ के लोगों का वर्चस्व हो रहा है । दूसरी बात उन्होंने यह कही कि भारत में संविधान बदलने की योजना बन रही है भारत का वर्तमान संविधान खतरे में है तीसरी बात उन्होंने यह भी कहीं कि भारत में लोकतंत्र को भी बदलने की तैयारी हो रही है भारत का लोकतंत्र भी खतरे में है। मैंने इन तीनों बातों पर गंभीरता से विचार किया। यह बात सच है कि भारत में लगातार संघ मजबूत हो रहा है क्योंकि संघ और हिंदुत्व एकाकार हो गए हैं सभी जगह से कम्युनिस्ट किनारे हो रहे हैं और संघ के लोग स्थापित हो रहे हैं लेकिन इसमें गलती किसकी है अगर विपक्ष मुसलमान कम्युनिस्ट विदेशियों को साथ लेकर भारत पर शासन करना चाहता है इसमें संघ गलत नहीं है हिंदुत्व गलत नहीं है गलत है तो विपक्ष। दूसरी बात यह है कि संविधान में बदलाव की तैयारी हो रही है इसमें क्या गलत है। यदि संविधान में संवैधानिक तरीके से बदलाव होता है तो राहुल गांधी उस बदलाव को कैसे रोक देंगे नेहरू खानदान ने संविधान में अब तक सैकड़ो बदलाव किया अब अगर नए तरीके से हम लोग दो-चार बदलाव करते हैं तो राहुल को कष्ट क्यों है क्या राहुल यह कह सकते हैं कि भविष्य में संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने लोकतंत्र पर कहीं यदि लोकतंत्र लोक स्वराज की दिशा में जाता है तो राहुल को कष्ट क्यों है क्या हम इस लोकतंत्र को जीवन भर ढोते रहे जो पश्चिम का सड़ा गला लोकतंत्र है । यदि उसके विकल्प के रूप में लोग स्वराज आता है तो राहुल को आपति नहीं होनी चाहिए । मेरे विचार से राहुल गांधी को यह बात भारत में और विशेष कर हिंदुओं के सामने रखनी चाहिए क्योंकि इसका समाधान भारत की जनता कर सकती है जर्मनी नहीं।

बजरंग मुनि

बांग्लादेश में हिंदुओं की पीड़ा और हमारी नैतिक जिम्मेदारी

@ **अनुराग पाठक**

बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, यह पूरे दक्षिण एशिया के अल्पसंख्यक समुदायों की असुरक्षा का आईना है। जिस तरह विरोध प्रदर्शन के दौरान उसे पीट-पीटकर मार दिया गया, उसके शव को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और फिर जला दिया गया, वह सभ्य समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य है। यह घटना बताती है कि भीड़ की हिंसा जब राजनीतिक और धार्मिक उन्माद से जुड़ जाती है, तो मानवता सबसे पहले मरती है।

दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमिशन के सामने हुए प्रदर्शन इसी पीड़ा और आक्रोश की अभिव्यक्ति थे। यह आक्रोश स्वाभाविक है। पड़ोसी देश में रहने वाले हिंदू केवल धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाए जा रहे हों और उनकी रक्षा के लिए राज्य तंत्र कमजोर या उदासीन दिखे, तो उसकी गूंज सीमाओं से परे सुनाई देती है। भारत में हुआ विरोध प्रदर्शन केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नजरअंदाज करने की कीमत क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में चुकानी पड़ सकती है।बांग्लादेश का जन्म धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के साथ हुआ था। 1971 के मुक्ति संग्राम की बुनियाद भाषा, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर रखी गई थी, न कि धार्मिक वर्चस्व पर। लेकिन समय के साथ वहां की राजनीति में कट्टरता का प्रभाव बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा हिंदू समुदाय को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी आबादी लगातार घट रही है। कभी जो समुदाय वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का अभिन्न हिस्सा था, वह आज भय और असुरक्षा में जीने को मजबूर है।

यह भी सच है कि किसी एक घटना को पूरे देश या समाज का चेहरा नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश में आज भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो ऐसी हिंसा के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल यह है कि राज्य की भूमिका क्या है। क्या दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई हो रही है। क्या अल्पसंख्यकों को यह भरोसा दिया जा रहा है कि वे इस देश के बराबरी के नागरिक हैं। अगर जवाब स्पष्ट नहीं है, तो समस्या गंभीर है।दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड टूटना और माहौल का तनावपूर्ण होना एक अलग पहलू है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विरोध शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहे। भावनाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसी संतुलन में एक जिम्मेदार राष्ट्र की पहचान होती है।

दूसरी ओर, बांग्लादेश द्वारा भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करना कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या ढाका अपनी जमीन पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उतनी ही गंभीरता दिखा रहा है। यदि नहीं, तो ऐसे कूटनीतिक कदम केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी एक देश का आंतरिक मामला भर नहीं रह जाती। मानवाधिकारों का सवाल अंतरराष्ट्रीय होता है। जब किसी समुदाय को उसकी पहचान के कारण निशाना बनाया जाता है, तो वैश्विक विवेक को बोलना पड़ता है। भारत, एक लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक रूप से विविध देश होने के नाते, इस मुद्दे पर संवेदनशील और संतुलित भूमिका निभा सकता है।भारत को चाहिए कि वह भावनात्मक बयानबाजी से आगे बढ़कर कूटनीतिक स्तर पर ठोस पहल करे। बांग्लादेश सरकार से स्पष्ट संवाद हो, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिंता दर्ज कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दोषियों को सजा मिले। साथ ही, दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संबंधों को कमजोर न होने दिया जाए, क्योंकि हिंसा की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं रिश्तों को होता है।

दीपू चंद्र दास की हत्या हमें याद दिलाती है कि धर्म, राष्ट्र और राजनीति से ऊपर मानव जीवन का मूल्य होना चाहिए। अगर हम इस मूल सत्य को भूल जाते हैं, तो कोई भी समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। आज बांग्लादेश के हिंदू असुरक्षित हैं, कल कोई और समुदाय होगा। इसलिए यह सिर्फ हिंदुओं का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता की साझा चिंता है।अंततः, सवाल केवल यह नहीं है कि दिल्ली में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ या ढाका ने क्या प्रतिक्रिया दी। असली सवाल यह है कि क्या इस घटना से कोई सीख ली जाएगी। क्या बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सम्मान देगा। और क्या क्षेत्र के देश मिलकर यह संदेश देंगे कि भीड़ की हिंसा और धार्मिक नफरत के लिए यहां कोई जगह नहीं है। अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक नहीं हुए, तो ऐसी घटनाएं बार-बार हमें शर्मिंदा करती रहेंगी।

जुबानी तीर

“ बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा चिंता का विषय है सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए।

प्रियंका गांधी वाड्रा (कांग्रेस नेता)

“ बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या अत्यंत निंदनीय और मानवाधिकारों पर सीधा हमला है। वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश सरकार को दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

जे.पी. नड्डा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी)

“ हमने बांग्लादेश के अधिकारियों को अल्पसंख्यकों पर हमलों पर अपनी कड़ी चिंता से अवगत कराया है और आग्रह किया है कि दास की बर्बर हत्या में शामिल दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।

विदेश मंत्रालय

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

त्वचा रोग का आयुर्वेदिक इलाज

त्वचा केवल शरीर का बाहरी आवरण नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना भी है। शरीर के भीतर चल रही गड़बड़ियां सबसे पहले त्वचा पर ही दिखाई देती हैं। दाने, खुजली, चकत्ते, फोड़े, दाग, एलर्जी, सोरायसिस, एक्जिमा या मुंहासे — ये सब सिर्फ बाहरी समस्या नहीं, बल्कि अंदरूनी असंतुलन का संकेत होते हैं। आधुनिक चिकित्सा में जहां त्वचा रोगों का इलाज अक्सर क्रीम, एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड तक सीमित रह जाता है, वहीं आयुर्वेद इन रोगों को जड़ से समझने और ठीक करने की पद्धति अपनाता है।

आयुर्वेद में त्वचा रोगों की समझ

आयुर्वेद के अनुसार त्वचा रोगों को "कुष्ठ रोग" के व्यापक वर्ग में रखा गया है। इसमें छोटे-बड़े सभी प्रकार के चर्म रोग शामिल हैं। आयुर्वेद मानता है कि त्वचा रोग मुख्य रूप से त्रिदोष — वात, पित्त और कफ के असंतुलन से होते हैं। विशेष रूप से पित्त दोष की भूमिका त्वचा रोगों में सबसे अधिक मानी गई है, क्योंकि पित्त का संबंध रक्त, ऊष्मा और रंग से होता है।

जब गलत खानपान, तनाव, नींद की कमी, प्रदूषण या रसायनयुक्त चीजों के कारण पित्त और रक्त दूषित हो जाते हैं, तो उसका असर सीधे त्वचा पर दिखता है। इसलिए आयुर्वेदिक इलाज केवल ऊपर से लगाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर को अंदर से शुद्ध करने पर जोर देता है।

त्वचा रोगों के प्रमुख कारण

आयुर्वेद के अनुसार त्वचा रोगों के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

विरुद्ध आहार का सेवन, जैसे दूध के साथ नमकीन या खट्टा

अधिक तला-भुना, मसालेदार और फास्ट फूड

अत्यधिक शराब या नशीले पदार्थ

दिन में सोना और रात में जागना

मानसिक तनाव, क्रोध और चिंता

कब्ज और कमजोर पाचन शक्ति

लंबे समय तक दवाइयों का सेवन

जब पाचन ठीक नहीं रहता, तो शरीर में "आम" यानी विषैले तत्व बनने लगते हैं, जो रक्त को दूषित करते हैं और त्वचा रोग पैदा करते हैं।

आयुर्वेदिक इलाज की तीन प्रमुख दिशाएं

आयुर्वेद में त्वचा रोगों का इलाज तीन स्तरों पर किया जाता है:

1. शोधन चिकित्सा (शरीर की शुद्धि)

यह आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें पंचकर्म पद्धति के जरिए शरीर से विषैले तत्व बाहर निकाले जाते हैं। त्वचा रोगों में विशेष रूप से विरेचन (पित्त शोधन) और रक्तमोक्षण का उपयोग किया जाता है। इससे रोग की जड़ कमजोर होती है।

2. शमन चिकित्सा (दोषों को संतुलित करना)

इसमें आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए बढ़े हुए दोषों को शांत किया जाता है। ये दवाएं शरीर के अंदर काम करती हैं और धीरे-धीरे रोग को नियंत्रित करती हैं।

3. आहार और जीवनशैली सुधार

आयुर्वेद मानता है कि बिना सही खानपान और दिनचर्या बदले कोई भी इलाज पूरी तरह सफल नहीं हो सकता।

त्वचा रोगों में उपयोगी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां

आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियां हैं जो सदियों से त्वचा रोगों में प्रभावी मानी जाती रही हैं:

नीमः रक्त शुद्ध करने में सबसे प्रभावी

मंजिष्ठाः त्वचा की रंगत सुधारने और दाग-धब्बे कम करने में सहायक

हल्दीः सूजन और संक्रमण को कम करती है

खदिरः खुजली और एलर्जी में उपयोगी

गिलोयः इम्यूनिटी बढ़ाकर त्वचा रोगों से लड़ने में मददगार

आंवलाः त्वचा को पोषण देता है और उम्र के असर को कम करता है

इन जड़ी-बूटियों का प्रयोग काढ़ा, चूर्ण, गोली या लेप के रूप में किया जाता है।

बाहरी उपचार का महत्व

आयुर्वेद बाहरी उपचार को भी नकारता नहीं है, लेकिन उसे सहायक भूमिका में रखता है। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा और सरसों या नारियल तेल से बने लेप त्वचा को राहत देते हैं। ये खुजली, जलन और सूजन को कम करते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमेशा अंदरूनी इलाज को प्राथमिकता देता है।

क्या खाएं:

हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन

हरी सब्जियां और मौसमी फल

मूंग की दाल, जौ और चावल

गुनगुना पानी

छाछ

क्या न खाएं:

बहुत ज्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन

दही और दूध का गलत समय पर सेवन

बासी और प्रोसेस्ड फूड

चीनी और मैदा

शराब और सिगरेट

मानसिक स्थिति का असर त्वचा पर

आयुर्वेद यह भी मानता है कि मन और त्वचा का गहरा संबंध है। तनाव, डर, गुस्सा और अवसाद त्वचा रोगों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए योग, प्राणायाम और ध्यान को इलाज का जरूरी हिस्सा माना गया है। अनुलोम-विलोम, भ्रामरी और ध्यान से मन शांत होता है और शरीर का संतुलन बेहतर होता है।

धैर्य और निरंतरता जरूरी

आयुर्वेदिक इलाज चमत्कार नहीं करता, बल्कि धीरे-धीरे स्थायी सुधार लाता है। त्वचा रोग जो वर्षों में बने होते हैं, उन्हें ठीक होने में भी समय लगता है। लेकिन आयुर्वेद का लाभ यह है कि इलाज बंद करने के बाद भी रोग दोबारा लौटने की संभावना कम होती है।त्वचा रोगों का आयुर्वेदिक इलाज केवल लक्षण दबाने का नहीं, बल्कि शरीर को फिर से संतुलन में लाने का प्रयास है। यह व्यक्ति की जीवनशैली, खानपान और मानसिक स्थिति को साथ लेकर चलता है। अगर सही मार्गदर्शन में और धैर्य के साथ आयुर्वेदिक उपचार अपनाया जाए, तो त्वचा रोगों से स्थायी राहत संभव है।आज जब रसायनयुक्त क्रीम और तात्कालिक राहत देने वाली दवाएं आम हो गई हैं, ऐसे समय में आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि असली इलाज हमेशा जड़ में होता है, सतह पर नहीं।

महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी भक्ति अमृत की दिव्य धारा

महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने सत्यरस और ब्रह्मानन्द के वितरण के लिए ही यह शरीर धारण किया था। उन्होंने आजीवन सत्य-ब्रह्म के शिवमय दिव्य सौंदर्य का चिंतन किया। असंख्य प्राणियों को अपने ब्रह्म-संगीत से मोहित कर लिया। निस्संदेह उनकी उपस्थिति से केवल श्यामला, कोमल कान्तिमयी स्वर्णिम वंगभूमि ही नहीं, बल्कि आसेतु हिमाचल की दिव्य गरिमा धन्य हो गई। वे रामकृष्ण और विवेकानन्द के समकालीन थे। योगी गम्भीरनाथ की साधना और तपस्या से पवित्र उत्तरापथ में विचरण कर उन्होंने ब्रह्म के दिव्य गान से भारत की धरती के कण-कण को पवित्र कर दिया। ब्राह्मसमाज के सिद्धांतों को भारतीय शास्त्र मर्यादा और भागवत चेतना की कसौटी पर कसकर उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संरक्षण तथा जागरण में महान सहयोग दिया। उन्होंने अपने समय की अध्यात्म-चेतना को भागवत रस से सम्पूर्ण सुलगावित कर दिया। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के उपदेशामृत-पान से उनकी अन्तरात्मा ज्योतिर्मय हो उठी। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने सत्य का साक्षात्कार किया। उनका जीवन भव-बंधन से मोक्ष और राष्ट्रीय अभ्युदय अथवा निर्माण का प्रतीक था। उनके जीवन का अधिकांश भाग बंगाल में ही बीता। वे महात्मा, भक्त और संत-सेवक के अद्भुत और असाधारण संन्वय थे। उनकी भक्ति की धारा ऐसी थी कि प्राणी मात्र उसके स्पर्श से ब्रह्मानन्द में डूब जाते।

अवतरण: सत्य-ब्रह्म का दिव्य गान

जन्म और कुल परम्परा: भागवत वंश की अमूल्य निधि

महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने परम भागवत कुल में जन्म लिया था। उनके पूर्वज चैतन्य देव के समकालीन परम वैष्णव, अद्भुत ब्रह्मानन्दी कृष्ण-भक्त अद्वैताचार्य महाशय थे। इन्होंने शांतिपुर में जन्म लेकर नवद्वीप धाम को अपनी सरस भगवद्भक्ति से गौरवान्वित किया। महाप्रभु चैतन्य की रसमयी लीला का विस्तार किया। उनके 'जीवे दया नामे रुचि' महामंत्र ने बंगाल को व्रज में परिवर्तित कर दिया था। विजय कृष्ण जी के शरीर में अद्वैताचार्य महाशय का पवित्र रक्त प्रवाहित था। अद्वैताचार्य महाशय की जीवन-कथा से उन्होंने अपार प्रेरणा प्राप्त की थी। वे ऐसे परम पवित्र कुल में भगवान की कृपा से जन्म प्राप्त कर अपने आपको अमित सौभाग्यशाली समझते थे। अपने पूर्वजों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा, असाधारण गौरवबुद्धि और पूज्य भावना थी। भगवद्भक्ति उनकी पैतृक संपत्ति थी। यह कुल ऐसा था मानो भक्ति का अमृत सरिता वहीं से निकल रही हो, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी दिव्य प्रेम की ज्योति जलाए चला आ रहा था।

बंगाल प्रांत के नदिया जनपद में परम पवित्र भगवती भागीरथी के तट पर शांतिपुर में उनका निवास स्थान था। विजय कृष्ण गोस्वामी जी के पिता आनंद किशोर लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम स्वर्णमयी था। दैवयोग से माता स्वर्णमयी अपने मायके गई हुई थी। स्वर्णमयी का मायका नदिया जनपद के शिकारपुर ग्राम के निकटवर्ती दहकूल ग्राम था। उन्होंने संवत् 1898 विक्रम में झूलन पूर्णिमा को (सन् 1841 ई., 2 अगस्त को) विजय कृष्ण गोस्वामी जी को जन्म दिया। शांतिपुर और दहकूल दोनों ग्रामों में प्रसन्नता और आनंद की बाढ़ आ गई। स्वजन और सगे-सम्बंधी नवजात के आगमन से हर्षित हो उठे। विजय कृष्ण जी के माता-पिता बड़े सात्विक स्वभाव के थे। उन्होंने अपने प्राणप्यारे पुत्र के सुचारु पालन-पोषण में अमित सावधानी का परिचय दिया। कभी विजय कृष्ण मामा के घर रहते थे तो कभी अपने घर शांतिपुर में रहते थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा का कोई निश्चित क्रम न था।

कभी वे शांतिपुर की पाठशाला में पढ़ने जाते थे तो कभी दहकूल के विद्यालय में शिक्षा पाते थे। बचपन से ही माता-पिता के सात्विक संपर्क के कारण साधु-संतों और देवी-देवताओं तथा भगवान में उनकी श्रद्धा बढ़ती गई। वे अद्भुत प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। यद्यपि देखने में बड़े चंचल थे पर स्वभाव कोमल और मधुर था। मन में दया का भाव था। घर में भगवान गोविंद देवकी पूजा होती थी। विजय कृष्ण बड़े प्रेम से अपने गृहदेवता गोविंद देव को साथ में खेलने के लिए बुलाया करते थे। और जब यह देखते थे कि भगवान नहीं आते हैं तब उन पर क्रोध प्रकट करते थे। इस प्रकार बाल्यावस्था में ही उनमें भगवान के प्रति विश्वास और जगत प्रेम की वृद्धि होने लगी। यह बाल लीला ऐसी थी मानो भगवान स्वयं उनके हृदय में खेल रहे हों, और वे उस दिव्य संग का आनंद लेने को व्याकुल हो उठते।

युवावस्था का आध्यात्मिक मोड़: कलकत्ता की विद्या और ब्राह्म दीक्षा

ग्राम पाठशाला का अध्ययन समाप्त होने पर संस्कृत के अध्ययन के लिए वे कलकत्ता आए। उन्हें हिंदू शास्त्रों के अध्ययन का सुंदर अवसर मिला। कलकत्ता के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के संपर्क में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनकी देवेन्द्रनाथ महर्षि से घनिष्ठता बढ़ गई। उनके उपदेशों से उन्हें आत्मज्ञान का प्रकाश मिला। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया। थोड़े समय के बाद उनका विवाह कर दिया गया। उनकी पत्नी का नाम योगमाया देवी था जो बड़ी सती-साध्वी और उदात्त चरित्र की रमणी थी। विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद भी महर्षि देवेन्द्रनाथ के उपदेशों से प्रभावित होकर ब्राह्म धर्म की दीक्षा ले ली और मेडिकल कॉलेज की शिक्षा छोड़ दी। महर्षि देवेन्द्रनाथ के मुख से निकले उपदेशों ने उनके हृदय में भागवत माधुर्य भर दिया। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने ब्राह्म समाज के लोगों में निर्मल भगवदुपासना-पद्धति का प्रचार किया। ब्राह्म समाज के मूल में लगे वैदेशिकता के कीड़ों का अंत कर डाला। पहले उन्होंने पूर्व बंगीय जनपद ढाका, खुलना, नोआखाली और मैमनसिंह आदि में ब्राह्मसमाज का प्रचार किया। जनता को नवीन ज्ञान-प्रकाश में भागवत चेतना दी। ब्रह्म-उपासना की विधि समझाई। उसके बाद केशव चंद्रसेन के साथ उत्तर-पश्चिम में प्रचार-यात्रा की। देश के कोने-कोने में ब्राह्म-समाज का प्रचार करना ही उनका जीवन-व्रत था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रचार-कार्य किया। वे कलकत्ता से शांतिपुर आते-जाते रहते थे। उन दिनों उनके मन में भगवद्भक्ति बड़े वेग से बढ़ रही थी। यह यात्राएं ऐसी थीं मानो वे भगवान के चरणों की खोज में ही भटक रहे हों, और हर कदम पर दिव्य प्रेरणा प्राप्त कर रहे हों।

शांतिपुर का दिव्य संयोग: चैतन्य भक्ति का जागरण

एक बार वे शांतिपुर आए हुए थे। उनके जीवन पर नवद्वीप के चैतन्यदास बाबा ने बड़ा प्रभाव डाला। शांतिपुर निवास-काल में महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी भगवान के भजन के लिए बड़े व्याकुल रहते थे। सदा भगवच्चिंतन में लगे रहना ही उनका दैनिक कार्यक्रम हो गया था। वे नित्य भागीरथी के तट पर वासंती ज्योत्सना में विचरण करते थे तथा उद्विग्न होकर अपने प्रेमास्पद की खोज करते थे। दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य की पवित्रता के नयन में आलोडन होते ही उन्हें अपने प्रियतम का स्मरण हो जाया करता था। एक दिन विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने अपने मन की भावना शांतिपुर-निवासी हरिमोहन प्रामाणिक के सम्मुख रखी। हरिमोहन ने उनके नव्यप्रेम से विशेष प्रसन्न होकर उन्हें पढ़ने के लिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ दिया। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी के हाथ में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का जाना था कि उनके रोम-रोम में अखंड और अतर्क्य भगवन्निष्ठा जाग उठी। जीव मात्र के प्रति दया, भगवन्नाम में भक्ति और रुचि तथा अनन्याश्रय की भावना से उनके विरहदग्ध हृदय को बड़ी शांति मिली। एक दिन विजय कृष्ण चैतन्य दास बाबा से मिलने गए। उनके साथ उनके भ्राता नीलकमल देव थे। उन्होंने बाबा से भगवद्भक्ति-लाभ का उपाय पूछा। चैतन्य दास बाबा के रोम-रोम सिहर उठे। उन्होंने बड़े प्रेम से विजय कृष्ण की ओर देखकर कहा कि भक्ति तो तुम्हारे ही घर की संपत्ति है। अद्वैताचार्य के वंशजों के रोम-रोम में भक्ति का निवास है। बाबा ने विजय कृष्ण से कहा कि यदि प्रेम-भक्ति के लाभ की मन में इच्छा है तो संसार के प्रति अनासक्त होकर दीन हीन और अकिंचन अवस्था का वरण कर लेना चाहिए। मन में अहंकार को एक कणिका भी रहने पर भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। विजय कृष्ण जी के मन पर चैतन्य दास बाबा के कथन का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में भगवद्भक्ति-प्राप्ति की आकांक्षा जाग उठी। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने भक्ति-व्रत ग्रहण किया। एक बार वे शांतिपुर से नवद्वीप जा रहे थे। रास्ते में कृष्णनगर के नगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय के घर वे ठहर गए। उन्होंने नगेन्द्रनाथ से कहा कि मुझे चैतन्य दास बाबा ने भक्तिपरक उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया। उन्होंने मुझे भोजन करने के लिए दिया। मेरे भोजन करने के उपरांत वे स्वयं मेरे पत्तल पर भोजन करने आए। मैंने निवेदन किया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मेरे पत्तल पर भोजन करना निषिद्ध है। चैतन्य दास बाबा ने कहा कि तुमने अद्वैत के वंश में जन्म लिया है, तुम परम भागवत हो। मैं उनके संपर्क से धन्य हो गया। यह संवाद भक्ति की गहराई को उजागर करता है, जहां विनम्रता ही दिव्य द्वार खोलती है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

ट्रम्प की सत्ता, पैसे का जाल और सवालों के घेरे में अमेरिकी राजनीति

@ आनंद मीणा

अमेरिका की राजनीति में पैसा हमेशा ताकतवर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद यह ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है, इसका अंदाजा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लंबी जांच से मिलता है। यह कहानी सिर्फ चंदे की नहीं है, यह कहानी सत्ता, पहुंच, फायदे और उन सवालों की है, जो लोकतंत्र की आत्मा को झकझोरते हैं।डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी टीम ने चुनाव प्रचार से भी ज्यादा बड़ा काम किया—बड़े पैमाने पर फंड जुटाना। जांच में सामने आया है कि चुनाव खत्म होने के बाद ट्रम्प और उनके करीबी लोगों ने करीब 2 अरब डॉलर, यानी लगभग 18 हजार करोड़ रुपये, अलग-अलग फंड और योजनाओं के लिए इकट्ठा किए। यह रकम उनके पूरे चुनाव अभियान में जुटाई गई राशि से भी ज्यादा है।

चुनाव के बाद भी क्यों इतना पैसा

आम तौर पर चुनाव खत्म होते ही फंडरेजिंग की रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन ट्रम्प के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उल्टा, चुनाव के बाद चंदा जुटाने की रफ्तार और तेज हो गई। सरकारी कागजात, फंडिंग रिकॉर्ड और कई दानदाताओं से बातचीत के आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि कम से कम 346 ऐसे बड़े दानदाता हैं, जिन्होंने हर एक ने ढाई लाख डॉलर या उससे ज्यादा का चंदा दिया।इन चुनिंदा दानदाताओं से ही करीब 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम आई। खास बात यह है कि इनमें से करीब 200 दानदाता ऐसे हैं, जिन्हें या जिनके कारोबार को ट्रम्प सरकार के फैसलों से सीधा या परोक्ष फायदा मिला।

भारतवंशी कारोबारी भी सूची में

इस सूची में टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम भी हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला समेत छह भारतवंशी बिजनेसमैन का नाम सामने आया है। ये वे लोग हैं, जिनकी कंपनियों पर सरकारी नीतियों का सीधा असर पड़ता है। हालांकि रिपोर्ट यह भी साफ कहती है कि यह साबित करना मुश्किल है कि किसी ने पैसा दिया और बदले में सीधा फायदा मिला, लेकिन इतना जरूर है कि पैसा और फैसलों का यह रिश्ता कई सवाल खड़े करता है।

फंड जुटाने का पूरा नेटवर्क

इन फायदों की तस्वीर काफी व्यापक है। किसी को राष्ट्रपति की तरफ से माफी मिली, किसी के खिलाफ चल रहे केस बंद हो गए, किसी कंपनी को अरबों डॉलर के सरकारी ठेके मिले, तो किसी को व्हाइट हाउस तक सीधी पहुंच मिल गई। कुछ दानदाताओं को सरकार में अहम पद भी दिए गए।यानी यह सिर्फ चुनावी चंदा नहीं था, यह सत्ता के करीब पहुंचने का रास्ता भी बनता दिखा।ट्रम्प की टीम ने फंड जुटाने के लिए कई रास्ते बनाए। सबसे बड़ा नाम है MAGA Inc., जो एक सुपर PAC है। अमेरिका में PAC ऐसे संगठन होते हैं, जो राजनीति के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और उम्मीदवार या पार्टी के समर्थन में खर्च करते हैं। नवंबर 2024 से जून 2025 के बीच MAGA Inc. ने करीब 200 मिलियन डॉलर जुटाए। इसके अलावा ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनी कमेटी ने करीब 240 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए, जो अमेरिकी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

व्हाइट हाउस का बॉलरूम और करोड़ों का चंदा

इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस में एक भव्य बॉलरूम बनाने के लिए भी दान लिया गया। ट्रम्प का दावा है कि इसके लिए करीब 350 मिलियन डॉलर जुट चुके हैं, हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने करीब 100 मिलियन डॉलर के दानदाताओं की पुष्टि की है। यह पैसा 'ट्रस्ट फॉर द नेशनल मॉल' नाम के संगठन के जरिए लिया जा रहा है।इसके अलावा अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए बने संगठन 'अमेरिका250', व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन और एक राजनीतिक समूह 'सिक्योरिंग अमेरिकन ग्रेटनेस' के लिए भी बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा किया गया।

दानदाताओं के नाम क्यों छिपे रहते हैं

इनमें से कई संगठनों में दान देने वालों के नाम सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। यही वजह है कि पूरा सिस्टम काफी हद तक गोपनीय बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प खुद इस बात पर नजर रखते हैं कि कौन कितना पैसा दे रहा है। उनकी फंडरेजिंग प्रमुख मेरिडिथ ओ'रूर्क उन्हें नियमित रूप से जानकारी देती हैं। कई लॉबिस्ट अपने क्लाइंट्स को सलाह देते हैं कि अगर ट्रम्प का ध्यान और व्हाइट हाउस तक पहुंच चाहिए, तो इन संगठनों को दान देना फायदेमंद हो सकता है।

दान और फैसलों का रिश्ता

रिपोर्ट में कई उदाहरण दिए गए हैं। एक महिला ने MAGA Inc. को 25 लाख डॉलर दिए। कुछ ही महीनों बाद उसके पिता को जस्टिस डिपार्टमेंट से रिश्वत मामले में बेहद कम सजा मिली।इसी तरह एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी पार्सन्स ने बॉलरूम प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख डॉलर दिए और बाद में वह ट्रम्प के 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे अरबों डॉलर के सरकारी ठेकों की दौड़ में शामिल हो गई।वीडियो गेम कंपनी रोब्लॉक्स के सीईओ ने भी बड़ा दान दिया और ट्रम्प की एआई नीतियों की खुलकर तारीफ की। एक दंपती ने शपथ समारोह और MAGA Inc. को मिलाकर करीब 15 लाख डॉलर से ज्यादा दिए। कुछ समय बाद उनके बेटे को फिनलैंड में अमेरिकी राजदूत बना दिया गया।

टेक और डिफेंस कंपनियों की भूमिका

टेक कंपनी पैलेंटिर ने बॉलरूम के लिए 1 करोड़ डॉलर और 'अमेरिका250' को 50 लाख डॉलर दिए। इसके बाद कंपनी को ट्रम्प सरकार से सैकड़ों मिलियन डॉलर के सरकारी ठेके मिले। इनमें इमिग्रेशन विभाग के लिए सॉफ्टवेयर बनाना भी शामिल है। कंपनी का कहना है कि इन ठेकों का दान से कोई लेना-देना नहीं है।डिफेंस कंपनियों लॉकहीड मार्टीन और बोइंग ने भी शपथ समारोह और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों डॉलर दिए। इसके बाद इन्हें फाइटर जेट और डिफेंस से जुड़े बड़े सरकारी फैसलों से फायदा मिला।कुछ मामलों में ट्रम्प ने दानदाताओं या उनसे जुड़े लोगों को राष्ट्रपति की माफी भी दी। एक इवेंट कंपनी के मालिक को, जिसकी कंपनी ने दान दिया था, बाद में ट्रम्प ने माफ कर दिया। इसी तरह MAGA Inc. को 10 लाख डॉलर देने वाली महिला के बेटे को टैक्स अपराध के मामले में माफी मिली।

क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों ने भी ट्रम्प समर्थित समूहों को लाखों डॉलर दिए। इसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ चल रही कई जांचें बंद कर दीं और क्रिप्टो के पक्ष में नीतियां अपनाईं। ऑयल, गैस और कोयला कंपनियों ने भी करोड़ों डॉलर का चंदा दिया और बदले में पर्यावरण नियमों में ढील और ड्रिलिंग की इजाजत मिली।

सत्ता के करीब रहने का फायदा

कम से कम 100 बड़े दानदाता ऐसे हैं, जो ट्रम्प के साथ व्हाइट हाउस में निजी डिनर में शामिल हुए, विदेश यात्राओं पर गए और राष्ट्रपति से सीधे मिले। कई बार सरकार की ओर से इन्हें सोशल मीडिया और प्रेस रिलीज में तारीफ के साथ दिखाया गया।व्हाइट हाउस ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि ट्रम्प का मकसद सिर्फ देश की भलाई है और दान देने वालों को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि कई कारोबारी डरते हैं कि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो कहीं राष्ट्रपति नाराज न हो जाएं। इसलिए कुछ लोग इस चंदे को एक तरह की सुरक्षा भी मानते हैं।

रक्षा के लिए मां से करें प्रार्थना

@ भारतश्री ब्यूरो

मां भगवती से अपनी रक्षा करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। शत्रुओं का भय नष्ट करने वाली जगदम्बिके ! मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्यकोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणि ! आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुण्डा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें।

वामभाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौंहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघण्टा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्यभाग में शखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शाकंभरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगन्धा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चण्डिका कण्ठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघण्टा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करें।

कण्ठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कण्ठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दण्डिनी और अंगुलियों में अम्बिका रक्षा करें शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें कुलेश्वरी कुक्षि अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विन्ध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें सम्पूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबलादेवी दोनों पिण्डलियों की रक्षा करें।

नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तैजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्राकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त को मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल-कोषों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणि, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें।

हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याणशोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गन्ध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमो गुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इन्द्राणि ! आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चण्डिके ! आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी सम्पूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवि ! जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हो।

माता के उत्कील पाठ से ही होता है कल्याण

यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना पाठ के कहीं एक पग भी न जाए। उत्कीलन, निष्कीलन, परिहार व शापोद्धार करने के बाद पाठ करके ही यात्रा करे। पाठ सम्पूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय को प्राप्त होती है। वह जिस-जिस अभीष्ट वस्तु का चिन्तन करता है, उस-उस को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलनारहित महान् ऐश्वर्य का भागी होता है। पाठ से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। गृह में उसकी पराजय नहीं होती तथा यह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह पाठ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होते। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु से रहित हो सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। देह का अन्त होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है।

समागम में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के महामंत्री व मंच संचालक श्री सुशील वर्मा 'गुरुदास' जी ने कहा कि यह ऐसा अद्भुत स्थान है जिसे भारत-पाकिस्तान सीमा का मालवा क्षेत्र कहा जाता है। यह बाबा फरीद की अद्भुत कृपाओं से भरा हुआ स्थान है। सतगुरु नानकदेव जी व अनेक सूफी संतों की कृपाओं, बलिदानों, प्रेम व शौर्य का स्थान है। यह स्थान निर्मल, शुद्ध प्रेम से भरा हुआ है जिसका क्या वर्णन किया जाए। इस फिरोजपुर क्षेत्र के श्रद्धालुओं की ओर से बार-बार प्रार्थना हुई और चौदह वर्ष बाद परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साक्षात दर्शन यहां हो रहे हैं। यहां इससे पहले 2011 में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साक्षात दर्शन हुए थे। सनातन ध र्म की एक अद्भुत घटना प्रयागराज में हुई। प्रयागराज महाकुंभ अनेक विषयों के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में श्रद्धालु इतनी अपार संख्या में आज तक कहीं और नहीं आए। इसी महाकुंभ में निरंजनी अखाड़ा जो तेरह अखाड़ों में सबसे प्रमुख माना जाता है, के परम पूजनीय संत स्वामी रविन्द्रपुरी जी महाराज के पावन सान्निध्य में एक अद्भुत आयोजन में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज को 'जगद्गुरु' की महाउपाधि से विभूषित किया गया। आज तक के इतिहास में ऐसी बहुत सी कृपाएं हुई हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया के विभिन्न चैनलों में देख सकते हैं।

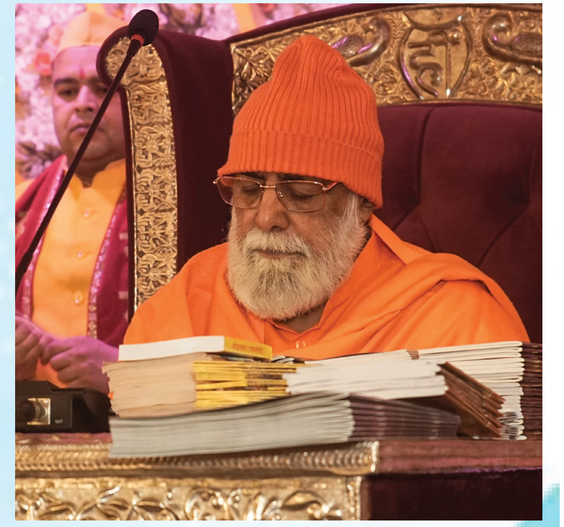

अरावली पर सियासी संग्राम

भ्रम बनाम तथ्य, पर्यावरण मंत्री ने साफ की तस्वीर

भूपेंद्र यादव बोले—एनसीआर में खनन की अनुमति नहीं, अरावली का कोर एरिया पूरी तरह सुरक्षित

@ सौम्या चौबे

देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली पर्वतमाला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इसकी सुरक्षा, परिभाषा और खनन से जुड़े सवालों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अरावली की परिभाषा में बदलाव कर बड़े पैमाने पर खनन का रास्ता खोला जा रहा है। सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। इसी विवाद के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष विस्तार से रखा और कहा कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।

अरावली हमारे देश की धरोहर

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अरावली के महत्व को रेखांकित करते हुए की। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला हमारे देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसका पर्यावरणीय संतुलन में बेहद अहम योगदान है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर गलत तरीके से भ्रम फैलाया गया है। भूपेंद्र यादव के मुताबिक उन्होंने स्वयं उस फैसले को पढ़ा है और उसमें कहीं भी अरावली को कमजोर करने या खनन को बढ़ावा देने की बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरावली की पहाड़ियों का दायरा घटा नहीं, बल्कि बढ़ा है।

कोर्ट का फैसला क्या कहता है

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अरावली को बचाने और इसे और मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि खासतौर पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण के लिए काम हुआ है। उन्होंने दिल्ली के ग्रीन बेल्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने राजधानी के आसपास हरित क्षेत्र को बचाने और बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। उनके मुताबिक कोर्ट का आदेश संरक्षण के पक्ष में है, न कि विनाश के।

एनसीआर में खनन की अनुमति नहीं

खनन को लेकर उठ रहे सवालों पर भूपेंद्र यादव ने साफ शब्दों में कहा कि एनसीआर क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि अरावली में बड़े पैमाने पर खनन की इजाजत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश में जिस "टॉप मीटर" का जिक्र है, वह न्यूनतम स्तर से जुड़ा हुआ विषय है।

इसका मतलब यह नहीं है कि पहाड़ियों को काटने या खत्म करने की छूट दी गई है। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। पर्यावरण मंत्री ने दोहराया कि अरावली का जो कोर एरिया है, वहां खनन की अनुमति है ही नहीं। यह क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित है।

सिर्फ 0.19 प्रतिशत हिस्से में पात्रता

अरावली पर्वतमाला के कुल क्षेत्रफल को लेकर भी भूपेंद्र यादव ने आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि अरावली का कुल क्षेत्र लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें से केवल 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है। उनके अनुसार इसका मतलब साफ है कि अरावली का 99 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह कहना कि अरावली को खत्म किया जा रहा है, तथ्यहीन और भ्रामक है।

क्या है पूरा विवाद

असल विवाद अरावली की परिभाषा को लेकर खड़ा हुआ है। एडवोकेट गांधी की ओर से लिखे गए एक पत्र की प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा को स्वीकार किया गया है। नई परिभाषा के अनुसार अरावली पहाड़ी उसे माना गया है जिसकी ऊंचाई अपने स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक हो। वहीं अरावली रेंज को ऐसी दो या उससे अधिक पहाड़ियों का समूह माना गया है, जो एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हों। यही परिभाषा विवाद की जड़ बन गई है।

पर्यावरणविदों की चिंता

पर्यावरणविदों का कहना है कि इस नई परिभाषा के चलते अरावली क्षेत्र का बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। उनका दावा है कि ऊंचाई आधारित यह नियम अरावली के करीब 90 प्रतिशत हिस्से को कमजोर कर सकता है। उनका तर्क है कि कई ऐसी पहाड़ियां और भू-आकृतियां हैं, जो 100 मीटर की ऊंचाई की शर्त को पूरा नहीं करतीं, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें जल पुनर्भरण क्षेत्र, जैव विविधता से भरपूर इलाके और निचली पहाड़ियां शामिल हैं।

गांधी की दलील

एडवोकेट गांधी ने अपने पत्र में कहा है कि 100 मीटर का नियम ऐसे कई अहम पारिस्थितिक क्षेत्रों को बाहर करने का खतरा पैदा करता है, जो भले ही ऊंचाई के आंकड़े पर खरे न उतरें, लेकिन पर्यावरणीय संतुलन के लिए जरूरी हैं। उन्होंने खास तौर पर निचली पहाड़ियों और पानी के रिचार्ज वाले इलाकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट को जन्म दे सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में अपील

एडवोकेट गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के बाद वर्तमान CJI कांत से अपील की है कि 20 नवंबर 2025 के आदेश में अपनाए गए परिभाषा फ्रेमवर्क पर फिर से विचार किया जाए या उसे और स्पष्ट किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि सिर्फ ऊंचाई पर आधारित मानदंड अपनाने से उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में पर्यावरण संरक्षण कमजोर पड़ सकता है। अरावली न सिर्फ एक पर्वतमाला है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के जलवायु और जल संतुलन की रीढ़ है।

संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला

अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए गांधी ने संविधान के कई प्रावधानों का हवाला दिया है। उन्होंने अनुच्छेद 21 का जिक्र किया, जो हर नागरिक को स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार देता है।इसके अलावा उन्होंने अनुच्छेद 48A का उल्लेख किया, जो राज्य को पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा का निर्देश देता है। साथ ही अनुच्छेद 51A(g) का हवाला दिया गया, जो नागरिकों पर पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य डालता है।

अरावली कितनी सुरक्षित?

एक तरफ सरकार का कहना है कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है और खनन को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम बेबुनियाद है। दूसरी तरफ पर्यावरणविद और कुछ कानूनी विशेषज्ञ इस नई परिभाषा को लेकर आशंकित हैं।सरकार का तर्क है कि कोर्ट के आदेश को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि आलोचकों का कहना है कि परिभाषा में छोटे से बदलाव का असर बहुत बड़ा हो सकता है।

अरावली पर्वतमाला का मुद्दा अब सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कानूनी, राजनीतिक और संवैधानिक बहस का विषय बन चुका है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जहां सरकार का रुख साफ कर दिया है, वहीं पर्यावरणविदों की चिंताएं भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस परिभाषा को लेकर कोई और स्पष्टता देता है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि अरावली को लेकर बहस लंबी चलेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ पहाड़ियों का नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

SIR में उलझे साधु, मजदूर और आम वोटर

चार करोड़ वोटर कहां गए?

@ मनीष पांडेय

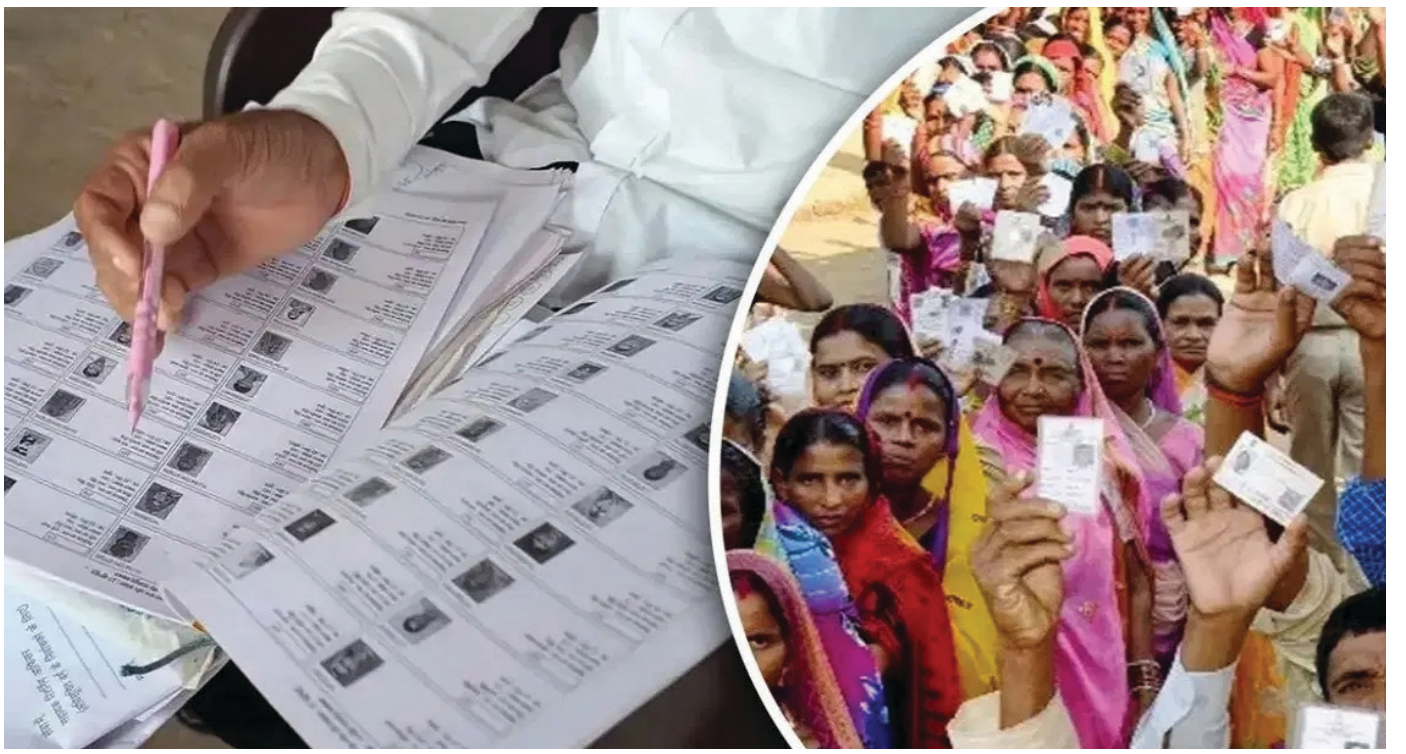

अयोध्या की गलियों में साधु-संतों का जीवन हमेशा से अलग रहा है। यहां त्याग है, वैराग्य है और सांसारिक रिश्तों से ऊपर उठ जाने की परंपरा है। लेकिन जब यही परंपरा वोटर लिस्ट के एक सरकारी फॉर्म से टकराई, तो मामला सिर्फ आस्था का नहीं रहा, लोकतंत्र का सवाल बन गया।अयोध्या के निर्वाणी अनी अखाड़ा के महंत सीताराम दास ने 10 दिसंबर को SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फॉर्म भरा। पिता के कॉलम में उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा और मां के स्थान पर जानकी माता का नाम दर्ज किया।

15 हजार साधु, हजारों एक जैसे फॉर्म

अयोध्या में करीब 15 हजार साधु-संत रहते हैं। निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अनी अखाड़ों से जुड़े इन संतों में से ज्यादातर ने SIR फॉर्म में पिता के नाम की जगह गुरु या किसी हिंदू देवता का नाम लिखा है। मां के कॉलम में कहीं कौशल्या, कहीं सीता, कहीं जानकी, तो कहीं दुर्गा और सरस्वती माता का नाम दर्ज है।संन्यास की परंपरा में यह बिल्कुल स्वाभाविक है। साधु-संत मानते हैं कि उन्होंने रक्त संबंध तोड़ दिए हैं। उनके लिए ईश्वर ही माता-पिता हैं।महंत सीताराम दास कहते हैं कि मैं पारिवारिक जीवन छोड़ चुका हूं। विरक्त परंपरा का पालन करता हूं। अब न मेरी कोई माता है, न पिता, न गोत्र। मेरे लिए ईश्वर ही सब कुछ हैं। जानकी माता पूरे जगत की मां हैं, इसलिए वही मेरी मां हैं।

CM योगी का दावा, 4 करोड़ वोटर गायब

SIR का फॉर्म आस्था और परंपरा नहीं देखता।नियम साफ है कि माता-पिता का नाम अनिवार्य है।यहीं से समस्या शुरू होती है। अगर फॉर्म अधूरा माना गया, तो नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। साधु-संत आमतौर पर BJP के वोटर माने जाते हैं, इसलिए पार्टी के भीतर भी चिंता गहराने लगी है।14 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी की वोटर लिस्ट से करीब चार करोड़ वोटर गायब हैं। उन्होंने BJP नेताओं से कहा कि ये लोग आपके विरोधी नहीं हैं, बल्कि 90 प्रतिशत आपके अपने वोटर हैं।CM योगी ने आंकड़ों के जरिए सवाल उठाया।यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है।65 प्रतिशत मतदाता होने चाहिए, यानी लगभग 16 करोड़ वोटर।लेकिन SIR में अब तक सिर्फ करीब 12 करोड़ वोटर ही सामने आए हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि यूपी में SIR की तारीख आगे बढ़ सकती है।

वोटर गायब हैं या फॉर्म रिजेक्ट?

चार करोड़ वोटर सच में गायब हो गए हैं या वे फॉर्म ही नहीं भर पाए।क्या फॉर्म गलत भरने की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं।क्या सिस्टम कुछ वर्गों को समझ ही नहीं पा रहा।इन सवालों के जवाब तलाशते हुए साफ होता है कि दिक्कत सिर्फ साधु-संतों तक सीमित नहीं है।SIR की जटिलताओं में प्रवासी मजदूर भी फंस रहे हैं।लखनऊ की फूलबाग झुग्गी बस्ती इसका उदाहरण है।यहां असम के करीब 50 मजदूर परिवार रहते हैं। कचरा बीनकर गुजारा करते हैं। 22 नवंबर को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिलों में घुसपैठियों की पहचान का अभियान शुरू हुआ। 4 दिसंबर को नगर निगम की टीम बस्ती में पहुंची और इन परिवारों को जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया।

आधार है, NRC है, फिर भी शक

फूलबाग बस्ती में रहने वाली कुलसुम निसा असम के गोलपाड़ा जिले की वोटर हैं। उनके पास आधार कार्ड और NRC के कागज हैं। फिर भी उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर डांटा गया।कुलसुम कहती हैं कि हमने कागज दिखाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बस कहा गया कि यहां अवैध रूप से रह रहे हो।उनके पड़ोसी इनताज अली भी यही सवाल उठाते हैं।हम भारत के नागरिक हैं। किराया देकर रहते हैं। फिर भी हमें घुसपैठिया कहा जा रहा है।

BJP के भीतर भी चिंता

BJP के अवध प्रांत से जुड़े एक वरिष्ठ नेता मानते हैं कि यह पार्टी के लिए गंभीर संकट है। उनका कहना है कि कई साधु-संत यह नहीं समझ पा रहे कि फॉर्म गलत भरने से नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। उन्होंने संत समाज से अपील की है कि वास्तविक माता-पिता का नाम भरें, लेकिन संन्यास की परंपरा के सामने यह अपील कमजोर पड़ जाती है। वहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि साधु-संतों के मामले में साइन को भी बड़ा प्रमाण माना जा रहा है और जरूरत पड़ने पर अलग विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। SIR का मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में अगर आस्था, गरीबी और प्रवास की सच्चाई छूट जाए, तो लोकतंत्र कमजोर होता है।

“दुनियाभर के हिंदुओं को आगे आना होगा”

कोलकाता से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

@ रिंकू विश्वकर्मा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दौरे पर हैं। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बांग्लादेश में जारी हिंसा और वहां हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर खुलकर चिंता जताई। भागवत ने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात बेहद कठिन हैं और ऐसे समय में दुनियाभर के हिंदुओं को एकजुट होकर उनकी मदद करनी चाहिए। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं में हिंदू समुदाय को भी निशाना बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में एक हिंदू युवक को बीच सड़क पर जिंदा जलाए जाने की घटना ने पूरे क्षेत्र में डर और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में मोहन भागवत का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है।

“वे वहां अल्पसंख्यक हैं, स्थिति कठिन है”

कोलकाता के कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां उनकी स्थिति लगातार मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में सबसे जरूरी है कि वहां रहने वाले हिंदू आपस में एकजुट रहें। एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मोहन भागवत ने कहा कि हालात आसान नहीं हैं, लेकिन अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को संगठित रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी हिंदू दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि वह आगे आए और हर संभव मदद करे।

“दुनियाभर के हिंदुओं को मदद करनी चाहिए”

संघ प्रमुख ने अपने बयान में अंतरराष्ट्रीय हिंदू समाज से भी अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जहां भी हिंदू रहते हैं, उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए जितनी भी मदद कर सकता है, उसे करनी चाहिए और वह कर भी रहा है। भागवत ने कहा कि “हमें वह सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं।” उन्होंने संकेत दिया कि इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं, हालांकि हर बात सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

सरकार की भूमिका पर क्या बोले भागवत

मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार की भूमिका पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है और ऐसे में भारत सरकार को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना होगा।उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ न कुछ करना ही होगा। संभव है कि सरकार पहले से ही इस दिशा में काम कर रही हो। कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं, जबकि कुछ अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।भागवत का यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भारत में लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष से लेकर सामाजिक संगठनों तक सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

बंगाल और सामाजिक एकजुटता का जिक्र

अपने संबोधन में मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो बंगाल में हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना उनका काम नहीं है। भागवत ने कहा कि संघ का काम राजनीति नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि RSS सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करता है और करता रहेगा।

“राजनीति नहीं, समाज हमारा क्षेत्र”

संघ प्रमुख ने साफ किया कि राजनीतिक बदलाव को लेकर निर्णय करना या टिप्पणी करना उनका दायरा नहीं है। उन्होंने कहा कि RSS एक सामाजिक संगठन है और उसका उद्देश्य समाज को संगठित करना है। सामाजिक एकता से ही किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब समाज मजबूत होता है, तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यही सोच संघ के कामकाज की आधारशिला है।

बांग्लादेश में हिंसा का पृष्ठभूमि

बांग्लादेश में हाल के दिनों में जिस तरह की हिंसा की खबरें सामने आई हैं, उन्होंने पड़ोसी देशों को भी चिंता में डाल दिया है। कई इलाकों से मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़ और हिंदू समुदाय के लोगों को डराने-धमकाने की घटनाओं की रिपोर्ट आई हैं। विशेष रूप से एक हिंदू युवक को जिंदा जलाए जाने की घटना ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला।

भारत में प्रतिक्रिया तेज

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है ताकि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।मोहन भागवत का बयान इसी कड़ी में एक मजबूत और स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने न केवल समस्या को स्वीकार किया, बल्कि समाधान की दिशा में एकजुटता और जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।

कोलकाता से दिए गए इस बयान के जरिए मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने समाज और सरकार दोनों से अपनी-अपनी भूमिका निभाने की अपील की। उनका कहना है कि एकजुट समाज सबसे बड़ी ताकत होता है और जब समाज साथ खड़ा होता है, तो सरकारें भी कदम उठाने के लिए मजबूर होती हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान कई मायनों में अहम है। यह बयान न सिर्फ चिंता जाहिर करता है, बल्कि जिम्मेदारी का अहसास भी कराता है।एक तरफ उन्होंने दुनिया भर के हिंदुओं से मदद की अपील की, तो दूसरी तरफ भारत सरकार से भी सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संघ राजनीति नहीं, बल्कि समाज के माध्यम से बदलाव लाने में विश्वास करता है।कोलकाता से दिया गया यह संदेश आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों और इस पूरे मुद्दे पर होने वाली चर्चा को नई दिशा दे सकता है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

दी हुई नींद

मैं ख़रिफ़ की फसल के बाद
सोऊँगा

सोऊँगा ज़रूर रबी की फसल के बाद
ललकारते खाली खलिहानों को

भर देने के बाद अन्न धन से
अन्न को अलगिया देने के बाद

पुआलों से
मैं होरहे की गंध के साथ सोऊँगा

बादल को न्योत लूँ पहले
सूर्य को दे लूँ अर्घ

घूर पर बार लूँ दिए
ता लूँ तमाम मूसों के बिल

फिर
फिर मैं सोऊँगा

मैं सोने के लिए ही तो करूँगा यह सब
कभी-कभी सोचता हूँ

कि यदि न आने वाली होती नींद
तो

तो मैं क्या जवाब देता
अपनी लड़बड़ी का

यदि न आने वाली होती नींद
तो क्या सचमुच कर रहा होता यह सब

तब मैं क्या सोच रहा होता
यह सब करते हुए

कितना बड़ा आशीर्वाद है भगवन्
तेरी यह दी हुई नींद!

अगली सदी तक हम

स्पंदन बचा है अभी
कहीं, किन्हीं, लुके छिपे संबंधों में

अन्न बचा है
अनायास भी मिल जाती हैं दावतें

ऋण है कि
बादलों को देखा नहीं तैरते जी भर

बरस चुके कई-कई बार
क्षमा है कि बेटियाँ

चुरा लेती हैं बाप की जवानी
उनकी राजी-ख़ुशी

जोश है बचा
कि रीढ़ सूर्य के सात-सात घोड़ों की ऊर्जा से

खींच रही है गृहस्थी
कहीं एक कोने में बचे हैं दुःख

जो तकियों से पहले लग जाते हैं सिरहाने
और नींद की अँधेरी घाटियों में

हाँकते रहते हैं स्वप्नों की रेवड़
पृथ्वी पर इन सबके चलते

बची है होने को दुर्घटना
प्रलय को न्योतते हुए

नहीं लजाएँगे अगली सदी तक हम।

अभिज्ञात
सुपरिचित कवि-कलाकार-पत्रकार

बॉन्डी बीच का खौफनाक हमला

इस्लामिक स्टेट की छाया में डूबा ऑस्ट्रेलिया

सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 को शाम के वक्त एक ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ, जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया। यहां हनुका का उत्सव चल रहा था, जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर यहूदियों का पवित्र त्योहार मना रहे थे। तभी दो हथियारबंद लोग एक सिल्वर ह्यूंडई कार से उतरे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी करीब 10 मिनट चली, जिसमें 15 लोग मारे गए और 25 से ज्यादा घायल हो गए। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची मैटिल्डा, 87 साल की होलोकॉस्ट सर्वाइवर और एक स्थानीय रब्बी भी शामिल थे। यह हमला ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे खतरनाक सामूहिक गोलीबारी हमला था, जो लगभग 30 साल पुराना पोर्ट आर्थर कांड के बाद सबसे बुरा साबित हुआ। घटना के वक्त बीच पर परिवार, बच्चे और पर्यटक मौजूद थे। कई लोग चिल्लाते हुए भागे, कुछ ने छिपने की कोशिश की। एक वीडियो में दिखा कि एक जोड़ा हमलावरों पर टूट पड़ा और एक की बंदूक छीन ली, जिससे और जानें बच गईं। यह शख्स अहमद अल अहमद था, जो एक आम नागरिक था लेकिन उसकी बहादुरी ने सबको प्रेरित किया। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर एक हमलावर को मार गिराया, जबकि दूसरा घायल हो गया। शुरुआत में इसे सामान्य गोलीबारी समझा गया, लेकिन जल्द ही पता चला कि यह एक सुनियोजित आतंकी हमला था, जो यहूदी समुदाय को निशाना बना रहा था। बॉन्डी बीच, जो शांति और सर्फिंग का प्रतीक था, अब फूलों की मालाओं और शोक सभाओं से भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इसे राष्ट्र के दिल पर चोट बताया और कहा कि यह नफरत का कृत्य है, जो हमारी एकता को चुनौती दे रहा है। इस हमले ने न सिर्फ परिवारों को तोड़ा, बल्कि पूरे देश में डर का माहौल बना दिया। लोग सोच रहे हैं कि कैसे एक खुशी का मौका इतना खतरनाक हो गया। जांच में पता चला कि हमलावरों की कार में बम और झंडे मिले, जो इस्लामिक स्टेट से जुड़े थे। यह खुलासा ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे शांतिप्रिय देश में आतंकवाद की जड़ें कैसे गहरी हो गईं, यह सवाल सबके मन में घूम रहा है। लेकिन इस दुख के बीच बहादुरी की कहानियां भी उभर रही हैं, जो उम्मीद की किरण दिखा रही हैं।

हमलावरों का रहस्य: पिता-पुत्र की काली साजिश

हमले के पीछे दो लोग थे – 50 साल के साजिद अकरम और उनके 24 साल के बेटे नवीद अकरम। साजिद को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया, जबकि नवीद घायल हालत में अस्पताल में है और उसे 15 हत्या के आरोपों समेत 59 मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं। ये दोनों सिडनी के बोनिरिग इलाके में रहते थे। साजिद का पासपोर्ट भारतीय था, जबकि नवीद का ऑस्ट्रेलियाई। जांच एजेंसी एएसआईओ ने 2019 में साजिद की जांच की थी, क्योंकि उसके सिडनी के एक चरमपंथी समूह से लिंक थे, लेकिन फिर उसे खतरा नहीं माना गया। नवंबर 2025 में दोनों फिलीपींस गए थे – मनीला से दावाओ तक। वहां इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क मजबूत हैं, और शक है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली हो। कार में मिले दो घरेलू बने आईएसआईएस झंडे और बम इसकी पुष्टि करते हैं। पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने कहा कि यह पिता-पुत्र की जोड़ी आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित थी, लेकिन किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती। साजिद का बैकग्राउंड रहस्यमयी है – कुछ रिपोर्ट्स में उसे भारत से जोड़ा गया, लेकिन भारतीय अधिकारी कहते हैं कि कोई सीधा लिंक नहीं। नवीद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था और सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन ऑनलाइन प्रोपगैंडा ने उसे बिगाड़ दिया। एक्स पर पोस्ट्स से पता चलता है कि आईएसआईएस ने हमले को सराहा और इसे यहूदियों के खिलाफ जिहाद बताया। ये दोनों कैसे इतने हथियार जुटा लाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के गन लॉ सख्त हैं? यह सवाल उठ रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि वे शांत थे, लेकिन अंदर से कट्टर हो चुके थे। इस जोड़ी ने न सिर्फ परिवार को बदनाम किया, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रेडिकलाइजेशन कैसे चुपके से फैलता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे लोग अकेले नहीं होते, बल्कि ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। फिलीपींस यात्रा ने जांच को अंतरराष्ट्रीय बना दिया, जहां आईएसआईएस के अवशेष सक्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया अब सोच रहा है कि क्या पुरानी जांचों को और गहरा करना चाहिए। यह केस दिखाता है कि आतंकवाद का चेहरा कितना सामान्य हो सकता है – एक पिता और बेटा, जो घर से निकलकर मौत बन जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई; अदालत में जवाब मिलेगा। समाज को यह सीखना होगा कि छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें।

आईएसआईएस की लंबी परछाईं: ऑस्ट्रेलिया में जहर कैसे फैला

इस्लामिक स्टेट, जो 2019 में सैन्य रूप से हार गया, फिर भी अपनी विचारधारा से दुनिया को डरा रहा है। बॉन्डी हमला इसका ताजा सबूत है। आईएसआईएस ने अपनी मैगजीन अल-नबा में हमले को 'सिडनी की शान' कहा और चेतावनी दी कि यह पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क में भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में आईएसआईएस का प्रभाव पुराना है – 2014 से 100 से ज्यादा लोग सीरिया-इराक गए थे लड़ने। यहां के मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग ऑनलाइन प्रोपगैंडा के शिकार बने। विशेषज्ञ ब्रूस हॉफमैन कहते हैं कि आईएसआईएस अब जमीन पर नहीं, बल्कि दिमागों पर राज करता है। बॉन्डी में यहूदियों को निशाना बनाना एंटी-सेमिटिज्म से जुड़ा, जो इजराइल-हमास जंग के बाद बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 16 महीनों में एंटी-सेमिटिक घटनाएं दोगुनी हुईं। आईएसआईएस के झंडे और बम मिलने से साफ है कि हमलावरों ने उनकी कॉल फॉलो की – यहूदियों और उनके समर्थकों पर हमला। लेकिन यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की समस्या नहीं; यूरोप में क्रिसमस मार्केट्स पर खतरा बढ़ गया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट कहती है कि आईएसआईएस की अपील कमजोर नहीं पड़ी, खासकर छुट्टियों के मौसम में। ऑस्ट्रेलिया में 2017 के मेलबर्न हमले से आईएसआईएस का लिंक साफ था। अब सरकार को सोचना है कि सोशल मीडिया पर कट्टरता कैसे रोकी जाए। मुस्लिम लीडर्स कहते हैं कि ज्यादातर समुदाय शांति चाहता है, लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं। एक्स पर बहस छिड़ी है कि क्या यह धर्म का नाम लेना सही है, या विचारधारा का मुद्दा। आईएसआईएस की छाया लंबी है क्योंकि यह गरीबी, गुस्से और अलगाव का फायदा उठाती है। बॉन्डी ने दिखाया कि एक वीडियो या मैसेज कैसे मौत का पैगाम बन जाता है। देश को अब सतर्क रहना होगा, ताकि अगला हमला न हो। यह जहर फैलाने वाले नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है, वरना शांति का सपना अधूरा रहेगा।

ऑस्ट्रेलिया का गुस्सा और एकजुटता: बहादुरी की मिसालें

हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दुख के साथ गुस्सा भी दिखाया। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने इसे 'हमारी एकता पर हमला' कहा और वादा किया कि नफरत को जड़ से उखाड़ा जाएगा। सरकार ने नई हेट स्पीच कानून लाने का ऐलान किया, जो नफरत फैलाने वालों को सख्त सजा देगा। गन कंट्रोल को और मजबूत करने की बात हो रही है, क्योंकि 1996 के पोर्ट आर्थर कांड के बाद ऐसे हमले रुक गए थे। बॉन्डी पवेलियन पर फूलों की चादर बिछी, जहां कैंडल लाइट विगिल हुए। यहूदी समुदाय ने कहा कि वे डरेंगे नहीं, बल्कि मजबूत होंगे। अहमद अल अहमद की कहानी वायरल हुई – उसने बंदूक छीनकर हीरो बन गया। बॉन्डी के लाइफगार्ड्स ने घायलों को बचाया, जो देश की बहादुरी दिखाते हैं। इजराइल, अमेरिका और यूएन ने समर्थन दिया। एक्स पर BondiStrong ट्रेंड कर रहा, जहां लोग एकता की बात कर रहे। लेकिन सवाल भी उठे – क्या इंटेलिजेंस फेल हुई? एएसआईओ चीफ ने एंटी-सेमिटिज्म को टॉप थ्रेट बताया। मुस्लिम और यहूदी लीडर्स ने मिलकर शांति रैली की, जो सकारात्मक संकेत है। प्रधानमंत्री ने अस्पताल जाकर अहमद से मिले और कहा, 'तुम असली ऑस्ट्रेलियन हो'। यह हमला दुखद था, लेकिन इसने समाज को जोड़ा। लोग समझ रहे हैं कि नफरत किसी एक समुदाय की नहीं, सबकी दुश्मन है। अब कानून बदलेंगे, लेकिन असली बदलाव दिलों में होगा। ऑस्ट्रेलिया साबित कर रहा है कि दर्द से ताकत निकलती है।

भविष्य की चुनौतियां: आतंक से लड़ने का सफर

बॉन्डी हमला खत्म नहीं हुआ, बल्कि नई शुरुआत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आईएसआईएस जैसे ग्रुप कमजोर हैं, लेकिन उनकी प्रोपगैंडा मशीन तेज है। ऑस्ट्रेलिया को अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना होगा, खासकर फिलीपींस और मिडिल ईस्ट से। साइबर सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी, ताकि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन रुके। युवाओं को एजुकेशन और जॉब्स देकर अलगाव कम करना जरूरी। एंटी-सेमिटिज्म के खिलाफ स्कूलों में प्रोग्राम चलेंगे। लेकिन चुनौती बड़ी है – कैसे एक फ्री सोसाइटी में स्वतंत्रता बचाते हुए सुरक्षा बढ़ाएं? यूएन के रैपोर्टर ने निष्पक्ष जांच की मांग की। एक्स पर बहस है कि क्या आईएसआईएस को ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा। समाज को संतुलन रखना होगा – नफरत न फैले, न डर। बहादुरी की कहानियां प्रेरणा देंगी।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

परमाणु ऊर्जा में निजी कंपनियों का खुला द्वार

शांति बिल की मंजूरी: एक ऐतिहासिक मोड़

भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शांति बिल को मंजूरी दी है। यह बिल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को जगह देने का रास्ता खोलता है। 60 साल से ज्यादा समय से यह क्षेत्र सिर्फ सरकारी नियंत्रण में था। अब निजी क्षेत्र इसमें निवेश कर सकेगा। शांति बिल का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे 2025 में पेश किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसे पास कर दिया। यह कदम भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी माना जा रहा है। वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,880 मेगावाट है। सरकार का लक्ष्य 2032 तक इसे 22,000 मेगावाट और 2047 तक 100,000 मेगावाट करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विकसित भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का हिस्सा है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान पर खर्च होंगे। 2033 तक कम से कम पांच ऐसे रिएक्टर चालू करने का प्लान है। यह बिल पुराने कानूनों को एक जगह लाता है। इससे लाइसेंसिंग आसान होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव ऊर्जा सुरक्षा लाएगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि निजी निवेश से तेजी आएगी, लेकिन सुरक्षा पर नजर रखनी होगी। अमेरिकी दबाव के आरोप भी लगे हैं, क्योंकि यह बिल विदेशी कंपनियों को 49 प्रतिशत तक निवेश की इजाजत देता है। कुल मिलाकर, यह बिल भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ता है। सरकारी पक्ष का मानना है कि कोयला और गैस प्लांट्स कम होने से परमाणु ऊर्जा जरूरी है। नेट-जीरो लक्ष्य 2070 तक हासिल करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। लेकिन विपक्ष चिंता जता रहा है कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया। क्या यह वाकई सभी के हित में है? यह सवाल समय के साथ साफ होगा।

फायदे और लक्ष्य: स्वच्छ ऊर्जा की नई उम्मीद

शांति बिल के फायदे लंबे समय के हैं। यह भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा कुल बिजली का सिर्फ 3 प्रतिशत है। लेकिन 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने से यह बढ़ेगा। निजी निवेश से सरकारी संसाधनों पर बोझ कम होगा। नवाचार आएगा और परियोजनाएं तेजी से बनेंगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर 20,000 करोड़ का खर्च से नई तकनीक विकसित होगी। ये रिएक्टर छोटे और सुरक्षित हैं। 2033 तक पांच चालू होंगे। नेट-जीरो लक्ष्य के लिए परमाणु ऊर्जा बेस-लोड पावर देगी। कोयला कम होने से प्रदूषण घटेगा। आर्थिक विकास होगा क्योंकि निजी कंपनियां रोजगार पैदा करेंगी। वैश्विक कंपनियां आएंगी, तकनीक साझा करेंगी। एनपीसीआईएल आधा लक्ष्य पूरा करेगा, बाकी निजी और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगा। जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। सरकारी बयान में कहा गया कि विकसित भारत के लिए यह मिशन जरूरी है। निजी क्षेत्र वैश्विक चेन में जुड़ेगा। अनुसंधान और कौशल पर फोकस होगा। लेकिन क्या ये फायदे सभी तक पहुंचेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचेगी। ऊर्जा आयात कम होगा। कुल मिलाकर, यह बिल ऊर्जा क्षेत्र को बदल देगा। लेकिन सफलता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। क्या सरकार इसे सुनिश्चित कर पाएगी? यह सवाल विचारणीय है।

बिल के मुख्य प्रावधान: निजी क्षेत्र को क्या मिलेगा?

शांति बिल के प्रावधान सरल लेकिन प्रभावशाली हैं। यह बिल परमाणु ऊर्जा से जुड़े पुराने कानूनों को एक साथ जोड़ता है। इससे नियामक अंतराल दूर होंगे और लाइसेंस प्रक्रिया सरल बनेगी। निजी कंपनियां अब परमाणु ईंधन का निर्माण, रूपांतरण, शुद्धिकरण और यूरेनियम-235 की समृद्धि कर सकेंगी। लेकिन यह सीमित स्तर तक ही। परिवहन, भंडारण, आयात-निर्यात और तकनीक का इस्तेमाल भी निजी हाथों में होगा। कंपनियां परमाणु पावर प्लांट बनाएंगी, चलाएंगी और बंद भी करेंगी। लेकिन संवेदनशील काम जैसे खर्च ईंधन का प्रबंधन, भारी पानी का उत्पादन सरकारी नियंत्रण में रहेगा। खर्च ईंधन को सरकार को सौंपना होगा या मूल देश को वापस भेजना होगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 प्रतिशत तक की अनुमति है। दायित्व के मामले में ऑपरेटर जिम्मेदार होंगे। न्यूक्लियर हादसे में अधिकतम 300 मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की जिम्मेदारी। प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसे मामलों में छूट मिलेगी। एक स्वतंत्र परमाणु सुरक्षा प्राधिकरण बनेगा। यह वैश्विक मानकों के अनुरूप काम करेगा। बीमा और सरकारी समर्थन से जिम्मेदारियां तय होंगी। खनन, उपकरण निर्माण और कुछ संचालन में निजी भागीदारी होगी। लेकिन फिसाइल सामग्री का उत्पादन सरकारी निगरानी में रहेगा। यह बिल निजी क्षेत्र को वैश्विक न्यूक्लियर इकोसिस्टम में जोड़ता है। अनुसंधान, वित्त, बीमा और कौशल विकास में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी। लेकिन क्या ये प्रावधान पर्याप्त हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि लाइसेंसिंग में एकीकृत प्रक्रिया से देरी कम होगी। फिर भी, खर्च ईंधन प्रबंधन पर सख्ती जरूरी है। कुल मिलाकर, यह बिल निजी कंपनियों को अवसर देता है, लेकिन सरकारी नियंत्रण बनाए रखता है। क्या यह संतुलन सही है? समय बताएगा।

चिंताएं और आलोचनाएं: सुरक्षा बनाम निवेश का संतुलन

शांति बिल पर चिंताएं भी कम नहीं हैं। विपक्ष का कहना है कि यह सुरक्षा को खतरे में डालता है। निजी कंपनियां लाभ के लिए जल्दबाजी कर सकती हैं। फुकुशिमा और चेर्नोबिल जैसे हादसों की याद दिलाते हुए आलोचना हो रही है। दायित्व सीमा 300 मिलियन एसडीआर तक है, लेकिन हादसे में नुकसान इससे ज्यादा हो सकता है। कौन भरेगा बाकी? नियामक प्राधिकरण की स्वतंत्रता पर सवाल हैं। क्या यह मजबूत होगा? विपक्ष ने कहा कि अमेरिकी दबाव से बिल आया। तीन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह नीति में यू-टर्न है। 2010 में भाजपा खुद विरोध करती थी। बिल को संसदीय समिति को भेजने की मांग हुई, लेकिन खारिज हो गई। पर्यावरण और मानवीय जोखिम बढ़ सकते हैं। खर्च ईंधन प्रबंधन पर सख्ती तो है, लेकिन निजी संचालन में गलतियां हो सकती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि लाइसेंसिंग में एकीकरण से निगरानी कमजोर पड़ सकती है। फ्रांस जैसा मॉडल सरकारी है, निजी क्यों? पारदर्शिता की कमी है। लेकिन सरकार का पक्ष है कि बहु-स्तरीय मुआवजा तंत्र है। बीमा और समर्थन से सुरक्षा होगी। फिर भी, क्या ये आश्वासन पर्याप्त हैं? जनता की सुरक्षा पहले होनी चाहिए। यह बिल निवेश लाएगा, लेकिन जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संतुलन बनाना चुनौती है।

क्या ढाका को लग गया मालदीव का 'मोइज्जू ज्वर'?

भारत-विरोध चुनावी दांव बन गया

बांग्लादेश में हलचल: हादी की मौत ने क्यों भड़काई हिंसा की लहर?

ढाका की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से आग की लपटें उठ रही हैं। 19 दिसंबर 2025 को, छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। हादी, जो अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, पिछले हफ्ते गोली लगने से घायल हुए थे। उनकी मौत के बाद ढाका और चटगांव जैसे शहरों में भारी बवाल मच गया। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया हाउस पर हमले किए, जैसे डेली स्टार की इमारत को आग लगा दी गई। संपादकों पर हमले हुए और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। यह सब कुछ महीनों के बाद हो रहा है जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि यह हिंसा सिर्फ हादी की मौत से जुड़ी है या कुछ और? विशेषज्ञ कहते हैं कि यह राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा है, जहां पुरानी दुश्मनियां नई आग में बदल रही हैं। हादी को 'जुलाई क्रांति' का शहीद माना जा रहा है, जिसने हसीना सरकार को उखाड़ फेंका था। उनकी मौत पर लोग गुस्से से सड़कों पर उतर आए, लेकिन जल्द ही यह गुस्सा व्यापक हो गया। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर पथराव हुआ, जो बताता है कि स्थानीय गुस्सा अब सीमा पार कर रहा है। अंतरिम सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह शांति बहाल करे, लेकिन यूनुस की टीम को लगता है कि यह सब 'इंजीनियर्ड' है, यानी सोची-समझी साजिश। एक तरफ छात्रों का आंदोलन लोकतंत्र की मांग कर रहा था, दूसरी तरफ अब इस्लामी समूहों की आवाज तेज हो रही है। यह माहौल फरवरी 2026 के चुनावों से पहले खतरनाक साबित हो सकता है। भारत जैसे पड़ोसी देश चिंतित हैं, क्योंकि यह हिंसा उनकी सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर, बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पुरानी जख्में फिर से हरी हो रही हैं, और लोग सोच रहे हैं कि क्या यह क्रांति का अंत है या नई शुरुआत।

भारत-विरोधी नारे क्यों गूंज रहे ढाका की गलियों में?

हादी की मौत के तुरंत बाद सड़कों पर 'भारत गो बैक' जैसे नारे सुनाई देने लगे। प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावासों के बाहर इकट्ठा हुए और संपत्ति तोड़ने लगे। क्यों? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हादी पर हमला करने वाला शख्स भारत भाग गया, जिससे लोगों में गुस्सा भड़क गया। लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि साल भर से पनप रही भावना का विस्फोट है। 2024 के चुनावों के बाद 'इंडिया आउट' कैंपेन फिर से जोर पकड़ चुका है, जो मालदीव की तर्ज पर चल रहा है। बांग्लादेश में लोग शेख हसीना के दौर को याद करते हैं, जब भारत का समर्थन उनकी सरकार को ताकत देता था। अब हसीना के जाने के बाद, नई ताकतें भारत को निशाना बना रही हैं। कुछ का मानना है कि यह पाकिस्तान या चीन की चाल है, जो क्षेत्र में भारत की पकड़ कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर, युवा पीढ़ी बेरोजगारी और आर्थिक दिक्कतों से तंग है, और भारत को दोष देना आसान रास्ता लगता है। एक्स पर चर्चाएं तेज हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि यूनुस सरकार इस्लामी रेडिकल्स को बढ़ावा दे रही है, जिससे एंटी-इंडिया सेंटिमेंट फैल रहा है। एक पोस्ट में लिखा था कि 'यह सब चुनाव टालने की साजिश है, ताकि यूनुस सत्ता में बने रहें।' भारत की तरफ से चिंता जताई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। लेकिन संतुलन देखें तो, यह सिर्फ भारत-विरोध नहीं, बल्कि आंतरिक राजनीति का खेल है। पार्टियां वोट बटोरने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रही हैं। क्या यह गुस्सा वाकई लोगों का है या नेताओं का हथियार? यह सवाल बांग्लादेश के भविष्य को छूता है। भारत को अब सतर्क रहना होगा, लेकिन बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। कुल मिलाकर, ये नारे सिर्फ शोर नहीं, बल्कि गहरी दरार के संकेत हैं।

मालदीव का आईना: मोइज्जू की चाल ढाका में क्यों काम कर रही?

मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू ने 2023 के चुनाव जीते भारत-विरोधी नारों से। उन्होंने 'इंडिया आउट' कैंपेन चलाया, भारतीय सैनिकों को निकालने का वादा किया, और चीन की तरफ झुके। नतीजा? मालदीव में भारत के पर्यटक 42 फीसदी कम हो गए, लेकिन मुइज्जू की सत्ता पक्की हो गई। अब बांग्लादेश में वैसा ही नजारा दिख रहा है। हादी की मौत के बाद एंटी-इंडिया लहर तेज हो गई, जो चुनावी मौसम में वोटों का दांव बन रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि दक्षिण एशिया में यह ट्रेंड बन गया है- पड़ोसी देशों में राष्ट्रवाद के नाम पर भारत को दुश्मन ठहराना। मालदीव की तरह, बांग्लादेश में भी युवा और इस्लामी ग्रुप्स इस भावना को हवा दे रहे हैं। 2024 में श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी भारत समर्थक सरकारें गिरीं, जिससे नई दिल्ली को झटका लगा। लेकिन फर्क यह है कि मालदीव छोटा द्वीप है, जबकि बांग्लादेश 17 करोड़ लोगों का देश। यहां की राजनीति ज्यादा जटिल है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'मालदीव ने सीखा, अब ढाका कॉपी कर रहा।' मुइज्जू ने अपनी जीत के बाद भारत से लोन लिया, लेकिन विरोध जारी रखा। बांग्लादेश में यूनुस सरकार भी ऐसा ही बैलेंस कर रही है- भारत से मदद लेना, लेकिन सड़कों पर नारे लगवाना। यह रणनीति वोटरों को एकजुट करती है, खासकर जब अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो। लेकिन खतरा यह है कि यह भावना अनियंत्रित हो जाए। भारत की सुरक्षा को ठेस पहुंचेगी, व्यापार प्रभावित होगा। संतुलित नजरिए से देखें तो, दोनों देशों के नेता घरेलू दबावों से जूझ रहे हैं। मालदीव का उदाहरण सिखाता है कि अस्थायी लाभ के चक्कर में लंबे रिश्ते खराब न हों। बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि क्या यह 'ज्वर' स्थायी बीमारी बन जाएगा?

फरवरी 2026 के चुनाव: भारत-विरोध टालमटोल का हथियार बनेगा?

बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव होने हैं, पहली बार हसीना के जाने के बाद। लेकिन हादी की मौत और हिंसा ने सबको सतर्क कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह सब 'मैनेज्ड कैओस' है, यानी नियोजित अराजकता, ताकि चुनाव टल जाएं। यूनुस सरकार पर दबाव है कि वह शांति लाए, लेकिन इस्लामी ग्रुप्स और पुरानी पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं। एंटी-इंडिया सेंटिमेंट यहां बड़ा रोल निभा रहा है। पार्टियां वोट बटोरने के लिए भारत को ब्लेम कर रही हैं, जैसे मालदीव में मुइज्जू ने किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा से चुनाव 'असुरक्षित' हो गए हैं। क्या यूनुस सत्ता लंबे समय तक थामना चाहते हैं? एक्स पर चर्चा है कि अमेरिका या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर, युवा बेरोजगारी से तंग हैं और नेता उन्हें गुमराह कर रहे। चुनाव आयोग को फैसला लेना होगा कि वोटिंग हो या न हो। अगर टली, तो अंतरिम सरकार मजबूत होगी, लेकिन लोकतंत्र कमजोर। भारत की चिंता वैध है, क्योंकि बांग्लादेश सीमा पर अस्थिरता उसकी सुरक्षा को खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ, बांग्लादेश को लगता है कि भारत हस्तक्षेप कर रहा। संतुलन बनाना जरूरी है- बातचीत से रास्ता निकले। चुनाव अगर हुए, तो नई सरकार को भारत के साथ बैलेंस रखना पड़ेगा। वरना, आर्थिक मदद रुकेगी। यह दांव बड़ा है, जहां वोटर सोचेंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। कुल मिलाकर, चुनाव अब सिर्फ वोटिंग नहीं, बल्कि देश की दिशा का फैसला बन गए हैं।

क्षेत्रीय रिश्तों पर असर: संतुलन की तलाश में दक्षिण एशिया

बांग्लादेश की यह हलचल सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं, पूरे दक्षिण एशिया को हिला रही है। भारत-बांग्लादेश रिश्ते पहले से तनावपूर्ण हैं, व्यापार 10 अरब डॉलर का है, लेकिन अब हमले बढ़ने से डर है। मालदीव की तरह, अगर एंटी-इंडिया राजनीति बनी रही, तो चीन को फायदा होगा। लेकिन संतुलित नजरिए से, दोनों देशों को फायदा सहयोग से है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की आजादी में मदद की, लेकिन अब पुरानी यादें भूल रही हैं। यूनुस सरकार को चाहिए कि वह रेडिकल्स को काबू करे, वरना पड़ोसी रिश्ते खराब होंगे। एक्स पर लोग कह रहे हैं कि यह ISI की चाल है, लेकिन सच्चाई जटिल है। दक्षिण एशिया में शांति के लिए बातचीत जरूरी। भारत को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन आक्रामक न बने। बांग्लादेश के लोग चाहते हैं स्थिरता, न कि नफरत। यह मौका है कि नेता सोचें- क्या दुश्मनी से कुछ मिलेगा? कुल मिलाकर, यह संकट सिखा रहा है कि पड़ोसी एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं।

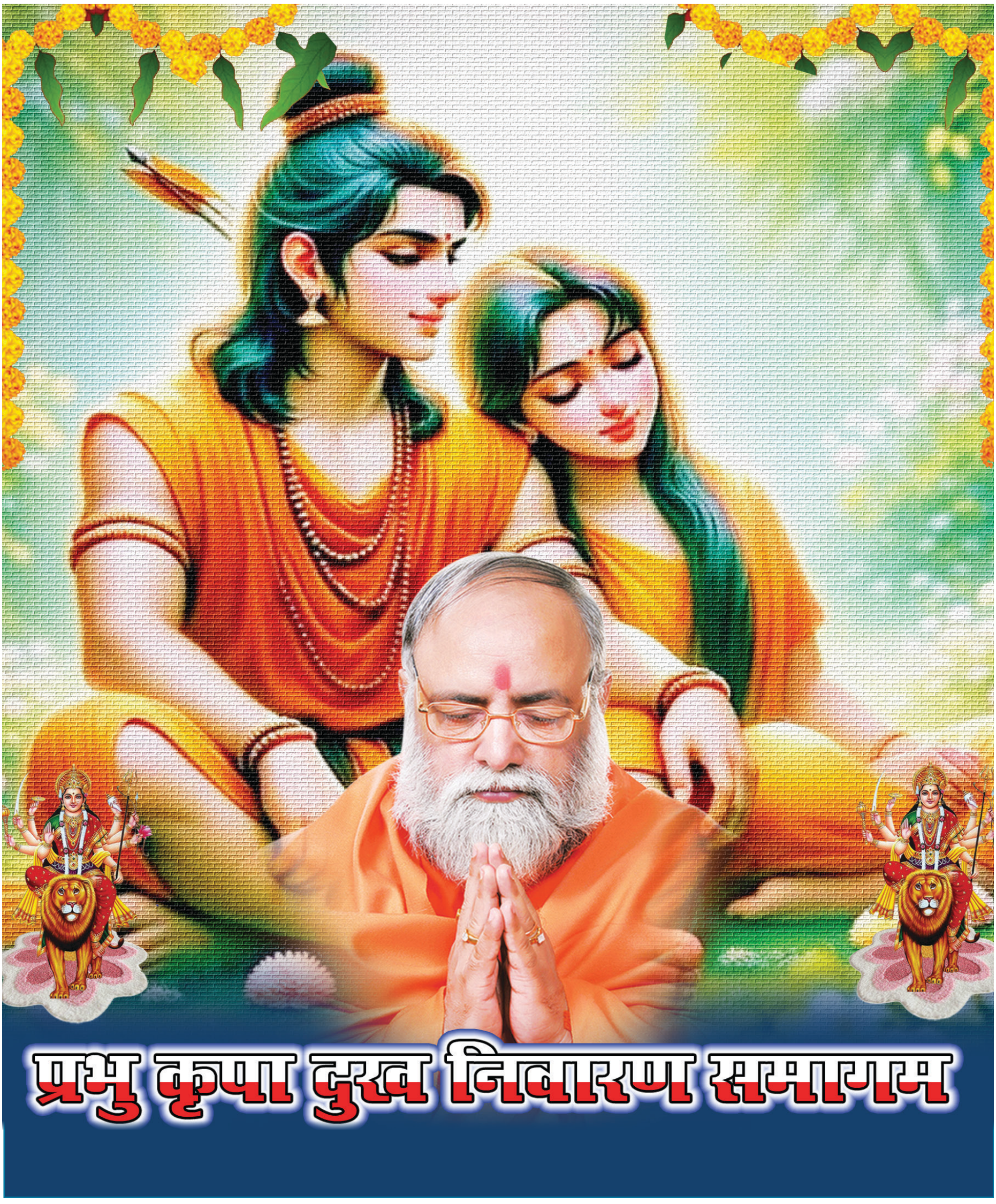
प्रभु कृपा दुख निवारण समागम

BY

Arihanta Industries

ULTIMATE HAIR SOLUTION

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

NO ARITIFICIAL COLOR FRAGRANCE CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries